Title Code UTTBIL 00553

केदारखाण्ड एक्सप्रेस

वर्ष : 1 अंक : 5 जुलाई-अगस्त-सितम्बर 2021 मूल्य : रू. 25

क्यों डरे हुए हैं उत्ताराखाण्ड के लोग

उत्ताराखाण्ड में कौन है विकल्प

संपादक : कुलदीप राणा 'आजाद'

15th AUGUST
HAPPY INDEPENDENCE DAY

समस्त देश–प्रदेश एवं रूद्रप्रयाग जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रदीप थपलियाल

प्रमुख क्षेत्र पंचायत जखोली

समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

आईए इस स्वतंत्रता दिवस संकल्प लें! राष्ट्र के विकास में कदम से कदम मिलाकर दे अपना योगदान। हमारा मकसद केवल विकास।

आशा नौटियाल

पूर्व विधायक

केदारनाथ विधानसभा

जनपद–रूद्रप्रयाग

समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

व्यापारियों के हितों के लिए हम हमेशा संघर्षरत हैं। व्यापारियों की एकता हमारी अखंडता का मूल मंत्र है। नगर को साफ एवं स्वच्छ रखें, यह शहर हमारी धरोहर है।

अंकुर खन्ना

जिला अध्यक्ष

उद्योग व्यापार मंडल रूद्रप्रयाग

सभासद : नगर पालिका रूद्रप्रयाग

समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

संतोष रावत

जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस रूद्रप्रयाग

सभासद : नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग

केदारखण्ड एक्सप्रेस

Title Code : UTTBIL 00553

वर्ष– 1, अंक– 5

जुलाई–अगस्त–सितम्बर 2021

संरक्षक

रमेश पहाड़ी, अनसूया प्रसाद मलासी

सम्पादक

कुलदीप सिंह राणा 'आजाद'

कानूनी सलाहकार

प्यार सिंह नेगी, पंकज चौधरी

प्रबन्धक : राकेश पंवार

ब्यूरो चीफ : भूपेन्द्र भण्डारी

रूद्रप्रयाग : वीरेन्द्र बर्त्वाल 'वीरेन'

चमोली प्रभारी :संदीप बर्त्वाल

गौचर :सोनिया मिश्रा

थराली :नवीन चंदोला

उखीमठ : भानु भट्ट

हरिद्वार : लखपत राणा

विशेष सहयोग : योगेश भट्ट

कवर फोटो : कमल जोशी वरिष्ठ छायाकार

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक कुलदीप सिंह राणा ने मंदाकिनी फोटोस्टेट एवं प्रिटर्स, रूद्रप्रयाग से मुद्रित कराकर जगवाण भवन, निकट पीएमजीएसवाई कार्यालय पोखरी रोड़, बेलणी रूद्रप्रयाग उत्तखण्ड से प्रकाशित।

सम्पादक : कुलदीप सिंह राणा

मो. 8958487822

सभी पद अवैतनिक हैं एवं सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रूद्रप्रयाग ही मान्य होगा।

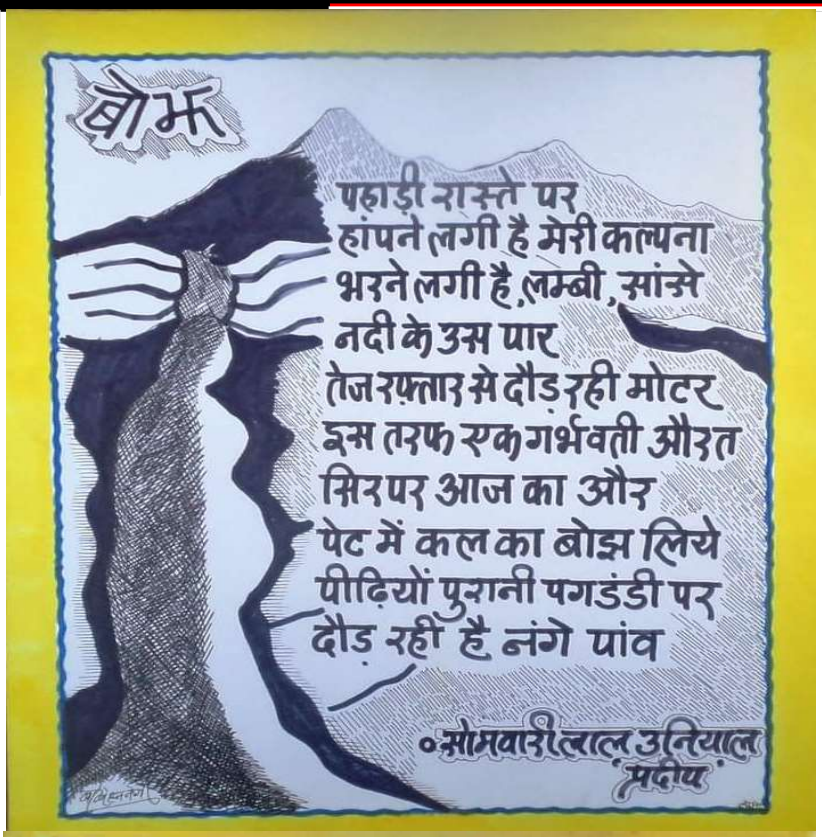

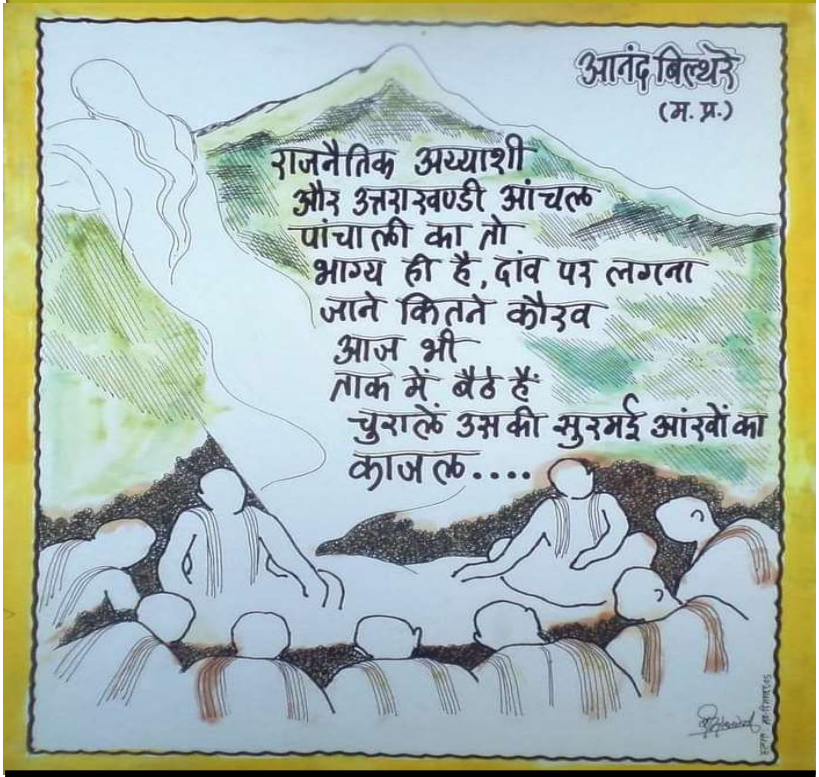

सम्पादकी कार्यालय

जगवाण भवन, निकट पीएमजीएसवाई कार्यालय, पोखरी रोड़, बेलणी रूद्रप्रयाग–246171, उत्तराखण्ड

email : kedarkhandexpress@gmail.com

www.kedarkhandexpress.in

उत्तराखण्ड मतलब 'प्रयोगशाला'

कुलदीप राणा आजाद
सम्पादक

उत्तराखण्ड राज्य के 21 वर्षों के सफर में 11 मुख्यमंत्रियों का 13 बार का कार्यकाल से न केवल राज्य के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा है बल्कि इससे विकास भी अवरूद्ध हुआ है और देवभूमि की छवि भी दागदार हुई है। जब–जब उत्तराखण्ड की राजनीति में अस्थिरता पैदा हुई है ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राजनीतिक दल जनता के लिए कोई बलिदान दे रहे हैं बल्कि भाजपा कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उत्तराखण्ड को 'प्रयोगशाला' बना दिया है।

एक लम्बी लड़ाई और दर्जनों शहादतों के फलस्वरूप जिन उद्देश्यों के साथ इस पर्वतीय राज्य का निर्माण हुआ था वह राज्य आज राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की प्रयोगशाला मात्र बनकर रह गई है। 21 वर्ष और 11 मुख्यमंत्रियों की पैदावार देकर जो राजनीतिक अस्थिरता भाजपा–कांग्रेस ने इस राज्य के भीतर किया है उसने इस राज्य की मूल अवधारणा को रसातल में धकेल दिया है। जबकि विकास के सवाल आज भी हाशिए पर हैं। साल 2000 में जब उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया था तो राज्य में भाजपा की अंतरिम सरकार बनी लेकिन पहले दो वर्षों में ही भाजपा ने दो मुख्यमंत्रियों का प्रयोग कर डाला। पहले नित्यानंद स्वामी और फिर भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। भाजपा को भरोसा था कि 2002 के आम चुनावों में जनता उन्हें पलकों पर बिठाएंगी लेकिन पहले ही विधान सभा चुनाव में जनता ने भाजपा को करारा जवाब दे दिया। सत्ता कांग्रेस को मिली तो उन्होंने नारायणदत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल तक सरकार चलाई। यह उत्तराखण्ड के अब तक के इतिहास में पहली स्थिर सरकार रही है। उसके बाद पुनः अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। 2007 के विधान सभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनी तो पहले भुवन चंद्र खण्डूड़ी फिर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और फिर भुवनचंद्र खण्डूड़ी पर भाजपा ने प्रयोग किया। लेकिन 2012 के विधान सभा चुनावों में फिर जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया, लेकिन एक ही थाली के चट्टे–बट्टे भाजपा–कांग्रेस कहाँ कोई पीछे रहने वाला था। 2012 मार्च में कांग्रेस ने पहले विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी और फिर फरवरी 2014 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन यहां भी पार्टी के ही भीतर बगावत का दौर चला और विधायकों का एक बड़ा खेमा भाजपा में शामिल हो गया, जिससे हरीश रावत की कुर्सी भी गिर गई। भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक खींचातान के कारण राष्ट्रपति शासन जैसा काला अध्याय भी इस राज्य के भीतर लगाया गया। हालांकि हरीश रावत ने जैसे तैसे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी खड़ी की लेकिन 2017 के विधान सभा चुनावों में कांग्रेस को जनता ने चारों खाने चीत कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जिस पार्टी पर जनता ने दोबारा भरोसा जताया और प्रचंड जनादेश दिया उसी पार्टी ने सत्ता हासिल कर जनता की भावनाओं को पैरो तले रौंध दिया और वहीं प्रयोगों का दौर शुरू कर दिया। पहले त्रिवेन्द्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई लेकिन चार साल बाद जब विकास को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कार्यशैली पर चौतरफा सवाल उठने लगे तो भाजपा ने एकाएक त्रिवेन्द्र को हटाकर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। लेकिन प्रयोगों का दौर यहीं नहीं थमा कुछ ही महीनों में तीरथ रावत को भी कुर्सी से हटाकर पुष्कर सिंह धाम को मुख्यमंत्री बना दिया।

ऐसा नहीं कि प्रयोग केवल मुख्यमंत्रियों पर ही किये जाते हैं बल्कि सरकारों के प्रयोग नौकरशाहों पर भी जमकर किए जाते रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य की पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भोगोलिक पारिस्थितियों के कारण विकास की गति कुंद पड़ी है। यहां कि विषम परिस्थितियों के कारण अधिकारियों को यहाँ की समस्याओं को समझने में वक्त लगता है बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादातर प्रशिक्षु जिलाधिकारियों को भेजा जाता है और सेवानिवृत्ति होने के लिए मुख्य विकास अधिकारियों को। वहीं जब तक जिलों में अधिकारी समस्याओं को समझ पाते तब तक उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। भ्रष्ट और निठल्ले अधिकारियों को सालों तक पहाड़ों में लूट–खसौट करने के लिए रखा जाता है। 'कोदा–झंगोरा खायेंगे उत्तराखण्ड बनायेंगे' जैसे नारे राजनीतिक शहमात के खेल में न जाने कहाँ दब गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाय तो 21 सालों में उत्तराखण्ड से पहाड़ पराया जैसा हो गया है। उत्तराखण्ड मात्र मैदानी क्षेत्र देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की तक ही रह गया है जिसकी शाखायें बिजनौर सहारनपुर तक जाने को उतावली हैं किन्तु जिस पहाड़ में उत्तराखण्ड की जड़ें हैं वहाँ से उत्तराखण्ड कट सा गया है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस पेड़ से जड़े अलग हो जाती हैं उसका सूखना और मुरझाना तय है। उसके बाद एक लेखक की पंक्तियां याद आती हैं–

जो खून बहा, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कैद हुए
हर कतरे का, हर गुंचे का, हर गीत का बदला मांगेगे....

उत्तराखण्ड में कौन है विकल्प?

योगेश भट्ट

विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी रण की बिसात बिछने लगी है। आम आदमी पार्टी की 'दस्तक' और उक्रांद की 'उछल कूद' के बीच अंततःमुकाबला सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। जहां तक मुददों का सवाल है तो पांच साल प्रचंड जनादेश की सरकार चलाने के बाद भाजपा खाली हाथ है । कांग्रेस के पास भी गिनाने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दों पर आक्रामक अंदाज में राजनीति करने वाली आम आम आदमी पार्टी भी नहीं है । मुद्दों की नब्ज पकड़ने के बजाय वह जनता की कमजोर नब्ज मुफ्तखोरी दबाकर अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है। कांग्रेस से आप तक और भाजपा से उक्रांद तक सियासत हर जगह चेहरों की है। भाजपा ने हाल ही में प्रचंड बहुमत की सरकार में चार माह में दो बार नेतृत्व परिवर्तन कर सरकार की कमान तीसरी पीढ़ी के युवा को सौंप कर बड़ा सियासी दांव चला तो जवाब में कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व के फार्मूले पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह की जुगल बंदी में 'चतुरंगिणी' सेना उतारी है।

दिवाकर और काशी सिंह ऐरी के बीच झूलने वाली उक्रांद कहीं दूर–दूर तक मुकाबले में नहीं है । वहीं तमाम गुणा गणित के बाद कर्नल अजय कोठियाल के सहारे, मुददों से बेखबर आम आदमी पार्टी सिर्फ प्रचार तंत्र के बूते उत्तराखंड की सत्ता का सपना देख रही है। जो बिसात बिछ रही है उसमें साफ है कि रण मुददों का नहीं बल्कि सिर्फ समीकरणों का है। जिस तरह आलू और प्याज की सब्जियों के सीमित विकल्प हैं ठीक वही स्थिति उत्तराखंड की सियासत की भी है। उत्तराखंड की सियासत का एक कड़वा सच यह भी है कि हम लाख क्षेत्रीय विकल्प की बात करें, लेकिन यहां की सियासत में वर्चस्व सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही है। अभी तक तो बारी–बारी से दोनों ही दल सत्ता में एक दूसरे का विकल्प बनते आए हैं। आम धारणा है कि दोनों ही दल जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। आमजन में दोनों ही दलों की रीति–नीति के प्रति नाराजगी भी है। नाराजगी क्यों न हो? बारी–बारी से सत्ता में आने के बावजूद दोनों ही दल दो दशक में राजनैतिक तौर पर इस राज्य की पहचान तक स्थापित नहीं कर पाए।

राज्य की अवधारणा और उसके भविष्य से जुड़ा हर अहम मसला दो दशक बाद भी अधर में लटका है। इसके बावजूद सियासी सच्चाई यह है कि सत्तर फीसदी से अधिक वोट बैंक इन दोनों ही दलों के कब्जे में है । सियासत की इस गुफ्तगू में भाजपा और कांग्रेस से पहले बात उन दलों की जिनका उत्तराखंड की सियासत में जिनका अपना तो कोई समीकरण नहीं बनता, मगर सियासी रण के प्रमुख योद्धाओं के समीकरण जरूर बना बिगाड़ देते हैं । पहले बात उक्रांद की.

UKD
उत्तराखंड क्रांति दल

नेताओं का मारा उक्रांद बेचारा

उत्तराखंड की सियासत में भाजपा और कांग्रेस का स्वाभाविक विकल्प चार दशक से भी अधिक पुराने एक मात्र क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को होना चाहिए था। विडंबना यह है कि राज्य की मूल अवधारणा को समझने वाले उक्रांद का नेतृत्व राजनैतिक विकल्प बनने का भरोसा नहीं जीत पाया। भाजपा जैसे बड़े राष्ट्रीय दल ने जहां राज्य में नेतृत्व तीसरी पीढ़ी के हाथों में सौंपना शुरू कर दिया है, वहीं उक्रांद दशकों बादभी अभी तक काशी सिंह ऐरी और दिवाकर भट्ट से आगे नहीं बढ़ पाया है । उत्तराखंड की सियासत में उक्रांद ऐसी अंधेरी रात बन चुका है जिसकी कोई सुबह नजर नहीं आती।

ऐसा नहीं है कि उक्रांद को मौका नहीं मिला। मौका मिला, राज्य गठन के बाद साल 2002 में पहले आम चुनाव में उक्रांद को चार सीटें भी मिली। उक्रांद का नेतृत्व ईमानदार और सियासी रणनीति मजबूत होती तो यह चार सीटें आज चालीस तक पहुंच सकती थीं।मगर कमजोर और स्वार्थी नेतृत्व के गलत निर्णयों के कारण दल की आम छवि बिगड़ती चली गई।साल 2007 में हुए आम चुनाव में दल ने तीन सीटें हासिल कर भाजपा के साथ सत्ता में भागेदारी की । सत्ता में भागेदारी पर सवाल उठा तो दल में विभाजन हो गया। किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि सत्ता के लालच में उसका शीर्ष नेतृत्व उसी दल से चुनाव मैदान में उतर जाए, जिसकी नीति रीतियों का दल विरोध करता रहा हो। उक्रांद खुद से छल करने वाले ऐसे नेताओं से खुद भले ही न्याय नही कर पाया हो लेकिन जनता ने पूरा न्याय किया। दल से अलग हुए शीर्ष नेता दिवाकर भट्ट कैबिनेट मंत्री रहते हुए 2012 में भाजपा से चुनाव लड़े और हार गए।

जहां तक दल का सवाल है तो विभाजित हो चुका दल उक्रांद (पी) के नाम से चुनाव में उतरा और 2012 में एक सिमट पर सिमट कर रह गया। उक्रांद (पी) से अकेले जीतकर आए प्रीतम पंवार भी कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए और पार्टी से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद साल 2017 में तो उक्रांद पूरी तरहसे साफ हो गई। आज राजनैतिक तौर पर उक्रांद हाशिए पर पहुंच चुका है, दल की कमान

थामे नेता पुराने ढर्रे पर हैं। न वे पिछली गलतियों से सबक लेने को तैयार हैं और न नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना की उनकी मंशा है। आज जब भाजपा और कांग्रेस नेतृत्व की कमान युवा हाथों को सौंप रही है, वही उक्रांद ने एक बार फिर से दिवाकर के बाद काशी सिंह ऐरी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। उत्तराखंड की सियासत को 'विकल्प' की तलाश है । सियासी तौर पर कोई कहीं भी जुड़ा हो, मगर यह सच है कि आम आदमी में एक छटपटाहट है। हर दूसरा व्यक्ति एक सशक्त विकल्प चाहता है। उक्रांद की नाकामी और कभी उक्रांद से काफी बेहतर स्थिति में रही बसपा के हाशिए पर पहुंचने के बावजूद विकल्प की संभावनाएं अभी भी हैं । इसी संभावना को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने संभवतः उत्तराखंड में 'दस्तक' दी है। मगर आप आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर पा रही है इसमें संदेह है । आज उत्तराखंड की सियासत से जुड़े तमाम सवालों के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आप उत्तराखंड की सियासत मैं आप तीसरा विकल्प बन पाएगी?

आप उत्तराखंड में आम आदमी की छटपटाहट को भांपते हुए सरकार बनाने का दावा तो कर रही है, सरकार बना सपने दिखा रही है, मुफ्त का लॉलीपॉप भी पकड़ा रही है, मगर सियासत का अंकगणित फिलवक्त इसके पक्ष में बनता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड की सियासत का अंकगणित यह है कि कम से कम तीस फीसदी वोट हासिल किए बिना सत्ता की चाबी हासिल नहीं की जा सकती। राज्य मैं तीस फ़ीसदी वोट हासिल करना भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के लिए आसान नहीं है । फिलहाल भाजपा के पास तकरीबन पैंतालीस फ़ीसदी वोट है तो कांग्रेस के पास भी तीस फीसदी वोट बना हुआ है । इस लिहाज से आप का सामीकरण सरकार तो दूर विपक्ष की लिए भी आसान नहीं है । उत्तराखंड की सियासत को भले ही विकल्प की दरकार है लेकिन यह सवाल तो बनता है कि आखिर 'आप' क्यों ?

आप : सत्ता का ख्वाब दिखानेवाला सॉफ्टवेयर

आमआदमी पार्टी दस्तक तो काफी पहले दे चुकी थी, लेकिन आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने उत्तराखंड में'री–लांच' किया है। 'रेडी टू ईट' के इंस्टेंट फार्मूले पर काम करने वाली आम आदमी पार्टी को सक्रिय हुए लगभग एक साल हो गया है।बीते साल भर में प्रचार तंत्र के जरिए पार्टी चर्चा में तो आई है लेकिन आम आदमी तक पहुंच नहीं। कारपोरेट की तर्ज पर काम करने वाली इस पार्टी में संगठन तो सिर्फ नाम भर का है। पार्टी के लिए सियासत एक इवेंट, चुनाव एक मैनेजमेंट और उम्मीदवार सिर्फ एक प्रोडेक्ट भर है। सीधे–सीधे 'गिव एंड टेक', मसलन उत्तराखंडमें तुम हमें सत्ता दो हम तीन सौ यूनिट फ्री बिजली देंगे।

सियासत में यह नई परंपरा है, जिसमें न कोई विचार है न आदर्श और न ही सिद्धांत। शुरूआती दौर में लगा कि आम आदमी पार्टी राजनैतिक शून्यता को खत्म करते हुए एक नया विकल्प बन सकती है, मगर पूरी तरह से प्रचार तंत्र पर निर्भरपार्टी जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आती है। दिल्ली में आप का फार्मूला जरूर कामकर गया लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड में बड़ा फर्क है। पार्टी यह भूल रही है कि उत्तराखंड दिल्ली नहीं है बल्कि विविधताओं वाला प्रदेश है। यहां संगठन, सिद्धांत, संघर्ष, आदर्श, विचार और व्यक्ति के अपने मायने हैं। हकीकत यह है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के भरोसे मैदान में उतरी पार्टी राज्य की विविधता,परंपरा, इतिहास, सामाजिक, राजनैतिक मुददों और संस्कृति तक से वाकिफ नहीं है। दिल्ली में हो सकता है यह आम आदमी की पार्टी हो मगर उत्तराखंड में तो यह सियासी महत्वाकांक्षाएं रखने वाले साधन संपन्न लोगों के लिएसियासी प्लेटफार्म बन कर रह गया है। साधन, संसाधन विहीन लोगों के आप में कोई मायनेनहीं। मायने होंगे भी कैसे ? मायने तो संगठन में होते हैं, विचार में होते हैं। जहां विचार और संगठन दोनों ही सिर्फ 'सत्ता' हो वहां तो यह उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल उत्तराखंड में यह आम आदमी की पार्टी नहीं बल्कि उन साधन संसाधन संपन्न लोगों कामंच बना है, जिनकी सियासी महत्वकांक्षाएं भाजपा और कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही हैं। सही मायने में कहा जाए तो आम आदमी

पार्टी सत्ता का ख्वाब दिखाने वाला एक 'सॉफ्टवेयर' है और सच्चाई यह है कि सॉफ्टवेयर का प्रचार कितना ही होबिना मजबूत 'हार्डवेयर' के वह काम नहीं करता। पार्टी से जुड़े चेहरों में अभी तक सिर्फ सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल एकमात्र वह बड़ा नाम है, जिसे हार्डवेयर माना जा रहा है।

यह 'हार्डवेयर' आम आदमी पार्टी के सॉफ्टवेयर के साथ कितने लंबे समय तक कदमताल कर पाएगा यह कहना मुश्किल है। ऐसे में राज्य की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली यह पार्टी नतीजों में कितना बेहतर करेगी, कहा नहीं जा सकता। हां, इतना जरूर है कि पहले आकलन था कि 'आप' उत्तराखंड में कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ेगी । कर्नल कोठियाल के आने के बाद आंकलन यह है कि कुछ सीटों पर आप अब आंशिक रूप से भाजपा को भी प्रभावित कर सकती है।

भूली बिसरी बसपा

जब हम उत्तराखंड में तीसरी ताकत की बात करते हैं तो आज बसपा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि भाजपा, कांग्रेस के बाद उत्तराखंड में तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक बसपा का है। विधानसभा में सीटों के लिहाज से बसपा आज हाशिए पर है , फिर भी यह नहीं नकारा जा सकता कि एक समय भाजपा बड़ी सियासी ताकत रह चुकी है। आज भी उत्तराखंड में बसपा के पास तकरीबन सात फ़ीसदी वोट है। आज भी हरिद्वार और उधमसिंहनगर जिलों में तकरीबन बीस फीसदी वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का है। एक समय ऐसा भी था जब 70 सीटों वाली विधानसभा में सात विधायक बसपा के थे। 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की नौ में पांच और उधमसिंहनगर जिले की सात में से दो सीटें

बसपा के पास थीं।

इन सात सीटों में से छहसीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं। साल 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में बसपा की ताकत और बढ़ी। इस चुनाव में बसपा के खाते में आठ सीटें आई। बसपा को नुकसान 2008 में हुए परिसीमन से हुआ। परिसीमन में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों में दो दो सीटें बढ़ने के बावजूद साल 2012 में हुए तीसरे विधानसभा चुनाव में बसपा कमजोर पड़ गई। पार्टी को उधमसिंह नगर की नौ सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली जबकि हरिद्वार में 11 में से सिर्फ तीन सीटों पर ही बसपा जीत दर्ज कर पाई। राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो बसपा की मजबूती का नुकसान हरिद्वार और उधमसिंनगर में कांग्रेस को रहा है। एक निश्चित वोट बैंक होने के बाद भी बसपा की स्थिति राज्य में दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। राज्य में संगठन की हालत यह है कि बीस साल में अब तक 17 बार प्रदेश अध्यक्ष और 13 बार प्रदेश प्रभारी बदल चुके हैं।

कभी किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली बसपा के पास विधायक तो दूर, जिला पंचायत तक में प्रतिनिधित्व नहीं है। समीकरण अब बदल चुके हैं, बसपा को पुनर्जीवन के लिए करिश्माई नेतृत्व की दरकार है जो फिलहाल उसके पास नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासत मैं भी विकल्प की दरकार बरकरार है। कुल मिलाकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की सांप सीढ़ी का खेल ही उत्तराखंड की 'नियति' है। चलिए, इस खेल पर एक नजर डालते हैं।

साल 2000 में जब उत्तराखंड बना तो राज्य में भाजपा की अंतरिम सरकार बनी। भाजपा को भरोसा था कि पहले आम चुनाव में जनता उसे पलकों पर बैठाएगी लेकिन नतीजे अप्रत्याशित रहे। साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 36 सीटें मिली तो तकरीबन सवा साल की अंतरिम सरकार में दो मुख्यमंत्री देने वाली भाजपा को जनता ने 19 सीटों पर समेट दिया। कांग्रेस खुद नतीजों पर भरोसा नहीं कर पाई थी। उस चुनाव में बसपा को सात और उक्रांद को चार के अलावा एनसीपी को भी एक सीट मिली जबकि तीन सीटें निर्दलीयों के नाम रही। पहली निर्वाचित सरकार कैसे चली और कैसी रही इस पर फिर कभी, परंतु यहां यह बताना जरूरी है कि अंतरिम सरकार से लगा राजनैतिक अस्थिरता का रोग पहली निवार्चित सरकार को भी लग चुका था। पूर्ण बहुमत की इस

सरकार में पूरे साल राजैनतिक अस्थिरता रही ।

यह बात अलग है उत्तराखंड के सियासी इतिहास में अभी तक एक मात्र यही सरकार ऐसी रही जिसमें पांच साल तक नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ। बहरहाल विकास के लिए जानी जाने वाली सरकार के प्रति नाराजगी रही होगी कि साल 2007 में दूसरे विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा को 69 सीटों में से 34 सीटें मिली जबकि कांग्रेस 36 से लुढ़क कर 21 सीटों पर आ गई। उक्रांद के तीन विधायकों और तीन निर्दलीयों का समर्थन हासिल कर भाजपा ने सरकार बनायी। भाजपा की इस सरकार में पांच साल में दो बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ। पूरे कार्यकाल के दौरान राजनैतिक अस्थिरता बनी रही और नतीजा यह रहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद साल 2012 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई।

खुद मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी को कोटद्वार विधान सभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। भाजपा और कांग्रेस में से किसी को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 32 सीटें और सत्ताधारी भाजपा को 31 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस ने तीन निर्दलीय विधायकों और उत्तरांखंड क्रांति दल (पी) के एक विधायक के समर्थन से सरकार बनाई। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश ने राजनैतिक अस्थिरता का चरम देखा। इस दौर में उत्तराखंड की सियासत एक काला अध्याय लिखा गया। नेतृत्व परिवर्तन हुआ, बगावत हुई, राष्ट्रपति शासन लगा, न्यायालय से सरकार की बहाली हुई, स्टिंग आपरेशन सामने आए, विधायकों की खरीद–फरोख्त के आरोप लगे, और भी बहुत कुछ हुआ। यही वह दौर था जब अपनी ही सरकार में कांग्रेस छिन्न–भिन्न हुई, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। अब राज्य में राजनैतिक अस्थिरता बड़ा मुददा बन चुका था। सियासत और सिस्टम दोनों इससे बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। साल 2017 में भाजपा ने एक ओर इस राजनैतिक अस्थिरता को मुददा बनाया और दूसरी ओर मोदी को चुनाव का चेहरा।

नतीजे इस बार भाजपा के पक्ष में रहे, जनता ने स्पष्ट और बड़ा जनादेश दिया। कुल 70 सीटों में से भाजपा को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमट कर रह गई तो वहीं बसपा और उक्रांद का पूरी तरह से सफाया हो गया। नियति देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद राजनैतिक अस्थिरता ने उत्तराखंड का पीछा नहीं छोड़ा। इस सरकार में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर तीरथ सिंह रावत और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी को सरकार की कमान सौंपी गई।

अब बात 2022 की। सत्ता की सांप सीढ़ी के खेल में अदल–बदल के लिहाज से 2022 में बारी तो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस की राह पहले जैसी आसान नहीं है। हालांकि जनादेश के लिहाज से तो भाजपा सरकार कटघरे में हैं। अंदरूनी सर्वेक्षणों में भी भाजपा की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। मगर इस सबके बीच भाजपा के लिए सुकून यह है कि कांग्रेस फिलवक्त बेहद कमजोर स्थिति में है। अगर सरकार में रहते हुए भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन नही कर पाई है तो यह भी उतना ही सच है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका भी प्रभावी नहीं रही। यह तो साफ है कि उत्तराखंड में सियासी रण चेहरों और समीकरणों का है। भाजपा

और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले में भाजपा मजबूत स्थिति में तो है मगर अजेय नहीं है। आम मतदाता का भी भाजपा से भरोसा दरक रहा है। हालात गंभीर हैं, इसका अंदाजा प्रदेश संगठन से लेकर भाजपा हाईकमान को भी है। संभवतरू इसी कारण पार्टी हाईकमान ने पांच साल में तीन बार मुख्यमंत्री बदलने का जोखिम उठाया। वह भी यह जानते हुए कि मुख्यमंत्री बदलने के सियासी प्रयोग को जनता खारिज करती आई है। फिलहाल उत्तराखंड की सत्ता में वापसी करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। एक बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री बदलने का यह प्रयोग कामयाब हो पाएगा ? हालांकि बदलाव और संक्रमण के दौर में स्थितियां इस बार कुछ अलग हैं। भाजपा ने प्रदेश में पुष्कर धामी के रूप में तीसरी पीढ़ी को सरकार का नेतृत्व सौंप कर बड़ा सियासी दांव चला है। जहां तक चेहरे का सवाल है तो मोदी का आज भी कोई विकल्प नहीं है और रही बात समीकरणों की तो उसके लिए भाजपा सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर किलेबंदी में जुटी है। भाजपा की किलेबंदी और समीकरण कांग्रेस की रणनीति के आगे कितने कामयाब होते हैं यह एक अलग विषय है।

अब आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा है राजनैतिक अस्थिरता। उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता भाजपा की कमजोर नब्ज है। राजनीतिक अस्थिरता से राजकाज तो प्रभावित होता ही है, तमाम और सवाल भी उठते हैं। विपक्षी कांग्रेस तो कह ही चुकी है कि भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदलती है। राजनीतिक अस्थिरता होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। राज्य में 40 फीसदी से अधिक वोट हासिल करने वाली भाजपा का नेतृत्व आखिर कमजोर क्यों है ? क्यों पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े ? क्यों प्रचंड बहुमत की सरकार राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाई ? क्यों राज्य में नेतृत्व नहीं उभर पा रहा है ? चाहकर भी इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। ये सवाल आम जनता या मतदाता को ही नहीं, भाजपा के कैडर को भी विचलित कर रहे हैं।

उत्तराखंड में भाजपा ने बीते चार महीनों में चार बड़े बदलाव की किए। चुनावी साल में त्रिवेंद्र को हटाकर तीरथ को मुख्यमंत्री बनाया, संगठन की कमान बंशीधर भगत से हटाकर मदन कौशिक को सौंपी, तीरथ को चार महीने पूरे करने से पहले ही हटाकर युवा चेहरे पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया और हरिद्वार से सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। पार्टी में इन फैसलों पर न सवाल उठे और न कोई विरोध हुआ। आलोचना, सहमति और असहमति से इतर इन चार फैसलों से यह तो साफ है कि भाजपा में पद और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। महत्व सिर्फ संगठन और दायित्व का ही है। मगर दूसरी और राज्य के नेताओं की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे। यह भी स्पष्ट हुआ कि राज्य का नेतृत्व कमजोर और अपरिपक्व है। मुख्यमंत्रियों को बदलना भाजपा के लिए कोई नया नहीं है। उत्तराखंड में तो भाजपा ने अपने हर शासनकाल में चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग किया है। दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री बदलने के सियासी प्रयोग को हर बार जनता ने खारिज किया है। तकरीबन ढाई दशक पहले भाजपा ने दिल्ली में भी पांच साल में तीन बार मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग किया तो वहां भी नाकाम रहा। तब दिल्ली में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने जैन डायरी में आने पर जब नैतिक तौर पर इस्तीफा दिया तो भाजपा ने पहले साहिब सिंह वर्मा और फिर लोकप्रिय नेता सुषमा स्वराज दिल्ली की कमान सौंपी। उस वक्त सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बावजूद दिल्ली में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।

अब तो स्थितियां बदली हुई हैं। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और विश्व का सबसे अधिक प्राथमिक सदस्यता वाला यह दल बदलाव और संक्रमण के दौर में है। संगठन बदलाव के दौर में है। जो भाजपा के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वह अब हो रहा है। अब रणनीतिक तौर पर भाजपा रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। अभी तक भाजपा नीति, रीति, विचार, सिद्धांत, राजनीतिक शुचिता, स्वच्छता और बूथ मैनेजमेंट के जरिए घर घर पहुंचने के लिए जानी जाती थी। अब भाजपा तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हुए काफी आगे निकल चुकी है। बदलाव का पार्टी को लाभ भी हुआ तो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अब बदलती भाजपा ने अपना कुनबा तेजी से बढ़ाया है। देश के तमाम राज्यों में सत्ता भी हासिल की है। उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल में ऐसे–ऐसे प्रयोग हुए जिनकी भाजपा में एक वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिनका भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस से तो दूर, कभी भाजपा तक से जुड़ाव नहीं रहा, उन्हें पार्टी में शामिल कर महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाते हैं। उत्तराखंड को ही लें, कांग्रेस सरकार के जिस मुख्यमंत्री को भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी करती रही उसे ही पार्टी में शामिल कर लिया गया। जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे, उन्हें ही अपनी सरकार में शामिल कर लिया गया। नुकसान यह रहा कि राज्यों में मजबूत नेतृत्व नहीं उभर पाया।

राज्यों में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता कहीं न कहीं इसी का दुष्परिणाम हैं। पार्टी में आंतरिक कलह और गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। पार्टी के लिए समर्पित रहे नेता और कार्यकर्ता कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हाशिए पर खड़े पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में निराशा घर कर गई है। कुल मिलाकर जो सियासी रोग और खामियां दूसरे दलों में थीं उनमें भाजपा भी जकड़ने लगी है। भाजपा को आसन्न चुनौतियों से पार पाने के लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में पिछले दिनों सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के दौरान उतार–चढ़ाव के बाद भाजपा ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ली है। खेल चेहरों का है । पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंप कर भाजपा हाईकमान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कांग्रेस भले ही यह कह रही हो कि भाजपा खिलौनों की तरह मुख्यमंत्री बदल रही है लेकिन हकीकत यह है कि धामी 'एक्सीडेंटल' नहीं बल्कि 'रणनीतिक' मुख्यमंत्री हैं। धामी के जरिए भाजपा ने अभी तक कांग्रेस के लिए मुफीद माने जा रहे कुमाऊं और तराई में हरीश रावत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार से तेजतर्रार नेता मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री के दायित्व से मुक्त कर संगठन की कमान सौंपकर और युवा नेता धन सिंह रावत को मजबूत कर क्षेत्रीय के साथ ही जातिगत संतुलन साधने की कोशिश की है।

बता दें कि 2022 के लिए भाजपा ने 60 सीटों का लक्ष्य रखा है। यह टारगेट बड़ा इसलिए है क्योंकि 57 सीटों पर तो भाजपा अभी है ही। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए यह आसान है और सब कुछ भाजपा की रणनीति के मुताबिक संभव है। भाजपा में भी दिक्कतें हैं। कुर्सी का संघर्ष, खेमेबंदी, सरकार और संगठन की रस्साकसी, नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहां भी बराबर है। कभी दो ध्रुवों में बंटी भाजपा में अब कई छोटे–बड़े 'मठ' स्थापित हो चुके हैं। सियासत के पुराने बरगद यहां भी नई पौध के आड़े आ रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाजपा की अंदरूनी कलह तो जगजाहिर है ही। फिलहाल भाजपा में किलेबंदी जारी है। नए मुख्यमंत्री पर कम ओवरों में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सधी बल्लेबाजी करने का दबाव है। शुरुआत अच्छी है मगर पूरा दारोमदार धामी के अगले सौ दिनों पर है। धामी सरकार के अगले सौ दिन सिर्फ भाजपा का ही नहीं बल्कि उनका भी सियासी भविष्य तय करेंगे।

हार के भय की छटपटाहट से निकला नया मुख्यमंत्री ?

जय प्रकाश पंवार

उत्तराखण्ड। भारी भरकम चुनावी जीत मिलने के बावजूद उत्तराखंड राज्य को अस्थिरता के भंवर में डालने के पाप से भारतीय जनता पार्टी को कैसे निजात मिलेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन जो मजाक भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ किया है इसका प्रतिफल तो पार्टी को मिलेगा ही. भाजपा ने पार्टी कैडर से जुड़े युवा नेता पुष्कर धामी को नया मुख्यमंत्री बना तो दिया है लेकिन अंदरखाने पार्टी के अन्दर घबराहट का दौर शुरु हो चूका है. बर्तमान विधायकों को कतई भी भरोसा नहीं लग रहा है कि धामी जी के नेतृत्व में पार्टी क्या सत्ता में वापस आ जायेगी. इसका सीधा सा अर्थ हुआ की विधायकों को अपने ही बलबूते पर चुनाव जीतकर आना होगा.

अब मोदी फैक्टर का करिश्मा भी पहले जैसा नहीं रहा. सबसे बड़ा गलत निर्णय भाजपा हाईकमान ने त्रिवेन्द्र रावत को हटाया, त्रिवेन्द्र पर ऐसे कोई गंभीर आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, सिर्फ ये कारण कि इनके नेतृत्व में भाजपा दुबारा वापस सत्ता में नहीं आ सकती. इसका भी नए मुख्यमंत्री तीरथ रावत को लाकर कोई समाधान नहीं था तो फिर त्रिवेन्द्र को क्यों बदला? आज राज्य में हर जगह यही चर्चा है. और अब पुष्कर धामी जैसे लो प्रोफाइल नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो भाजपा क्या सन्देश देना चाहती है. कुल मिलाकर भाजपा पार्टी हाईकमान गलती पर गलती करती जा रही है. और इस वजह से उत्तराखंड भाजपा गर्त की और यानी हार की और कदम दर कदम बढाती जा रही है. और कांग्रेस बैठे बिठाये सत्ता की और आगे सरकती जा रही है. जैसे दृ जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस से भाजपा में आये विधायको मंत्रियों में छटपटाहट पहले से ही थी पर अब बैचौनी बढ़ गयी है.

युवा धामी को मुख्यमंत्री बनाकर यह स्पस्ट कर दिया गया है कि अब तुम चाहे कितने ही सीनियर हो, कदावर हो तुमारे लिये भाजपा में कोई स्कोप नहीं रह गया है. तीरथ मंत्रिमंडल में बुजुर्ग विधायकों जैसे बंसीधर भगत, बिसन सिंह चुफाल को मंत्रिमंडल में शामिल करना भी यही संकेत था. जहाँ तक योग्यता की बात है भाजपा में इसकी कोई मान्यता नहीं है. नहीं तो मुन्ना सिंह चौहान जैसे लोग खाली हाथ नहीं बैठे होते. भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है वो कैडर को लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है तब वो चाहे तीरथ हो या धामी. अब भाजपा में हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य आदि जैसे नेताओं के लिये इस बार तो मंत्री भी बन गए अगली बार ले दे कर विधायक बन भी गए तो मंत्री बनने के लाले पड़ने वाले है. अब इन नेताओं की छटपटाहट और बढ़ गयी है. पिछले काफी समय से अंदरखाने सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि ये सब लोग पाला बदलने की फ़िराक में है।

ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों की अदला बदली से उपजे हालातों से राज्य व केंद्र के भाजपा के नेता अनभिग्य है, बर्तमान हालातों ने पार्टी को मजबूर कर दिया है कि अब चाहे जीते या हारें पर होगा अपना कैडर का ही नेता. नहीं तो भाजपा के पास आज भी ऐसे जीताऊ नेता थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था व जो पार्टी को दुबारा सत्ता दिलाने में सहायक हो सकता था. अथरू भाजपा को एक बार फिर उत्तराखंड में मोदी के ही भरोसे चुनाव में उतरना है.

धामी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कांग्रेस के कदावर नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी साधना है व कुमाओं को यह सन्देश देना था कि पार्टी ने बहुत समय बाद ही सही कोश्यारी के बाद कुमाओं को भी धामी के रूप में मुख्यमंत्री दे दिया है. भाजपा को हरीश रावत के नाम से अभी से पसीने छुटने लगे है, यह यही संकेत है की अंदरखाने पार्टी का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है. भाजपा भले ही सल्ट से जीत गयी हो लेकिन तीरथ को वहां से जिताने की पार्टी की हिम्मत नहीं हो पायी न खुद तीरथ को वहां से जीतने का भरोषा था, जब गंगोत्री की बाते चली तो वहां भी तीरथ के जीतने की संभावना नहीं लगी, तो भाजपा को हार का इतना डर लगा कि संवेधानिक संकट का बहाना लेकर मुख्यमंत्री को ही बदलना पड़ा. सत्ता के मोह में चूर भाजपा ने यह योजना नहीं बनायी कि सबसे पहले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी विधायक बनवा लिया जाये व जनता को अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला जाये. प्रदेश को ८ मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी किस मुह से चुनाव में जाने वाली है. इसका सामना पार्टी को आने वाले चुनाव में करना होगा. नए मुख्यमंत्री से कोई चमत्कार होगा ऐसी फिलहाल जनता को आशा नहीं है. ५७ विधायको को जनता ने चुनकर भाजपा को दिया और उसका हस्र ये रहा कि एक ढंग का मुख्यमंत्री तक पार्टी नहीं दे पायी व राज्य को बार – बार अस्थिरता के दौर में ले गयी. उत्तराखंड को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने वाले भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व को यह तो समझना होगा की विधायकों को तो आप चुप करा सकते हो लेकिन जनता की भावनाओं से खेलकर जो पाप आपने किया है उसके भुक्तभोगी भी आप ही होंगे न भाजपा का कार्यकर्त्ता और न ही जनता।

हमारी विकास यात्रा

मनमीत

पिछले दिनों अखबारों के पहले पेज पर एक खबर फड़फड़ा रही थी। देहरादून से टिहरी झील तक 35 किलोमीटर की सुरंग का निर्माण होगा। अभी अखबार की उस खबर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि उस सुरंग से ऊपर जो नई नई ऑल वेदर सड़क बनाई गई, वो ही बेवक्त मर गई। आज से लगभग छह साल पहले इस ऑल वेदर रोड की जब योजना बनाई गई थी तब भी अखबारों में खबर फड़फड़ा रही थी। सरकार ने दावा किया कि ये एक ऐसी सड़क होगी, जो 12 महीने जिंदा रहेगी। जलजला आ जाये या तुफान, बाढ़ आ जाये या चक्रवात। सबको ये सड़क झेल लेगी। खैर प्राकतिक आपदाओं को तो ये ऑल वेदर रोड नहीं झेल पाई, लेकिन देश के कुछ चुनिंदा ठेकेदारों, नेताओं और अधिकारियों की जिंदगी ऑल वेदर रॉड ने चकाचक बना डाली।

बहुत साल पहले, मुझे याद है जब हम देहरादून या ऋषिकेश में बस में बैठकर पुरानी टिहरी जाया करते थे। ऋषिकेश की तपती गर्मी से पहली राहत आगराखाल में सुर सुर बहती हवाओं से मिलती। ठसाठस भरी बस आगराखाल में किसी ढाबे के बाहर रूकती और कंडक्टर बोलता, यहां पर बस बीस मिनट रूकेगी। हम बच्चों को ये कंडक्टर का आदेश खुश कर देता। चाय पकोड़े खाने के बाद बस आगे चलती और धीरे धीरे गंतव्य में पांच घंटे में पहुंच जाती। फिर जब बढ़े हुये तो अपनी कार से इसी रास्ते से आगराखाल पहुंचते और भुटवा भात खाते। कभी कभी नागनी में साथ बहती गाड़ के सफेद पानी मे हाथ मुँह धो लेते तो कभी सड़क के दोनों और पेड़ों की छत पर सुस्ता लेते।

फिर एक दिन नेताजी को लगा कि हम खुश नही हैं। वो अपने साथ ऑल वेदर रोड को बनाने ठेकेदार और अधिकारी ले आये। सभी हाथ में बेलचा और सब्बल लेकर पहुंचे। उन्होंने हजारों पेड़ काट डाले और पहाड़ों को बेतरतीब छिलकर सड़क को चौड़ा कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि अब तुम दून से फर्राटा भरकर अपने घर पहुंचोगे। हमने मान लिया। कुछ नहीं माने तो उन्हें हमने मनवा लिया। जो बिल्कुल भी नहीं माने उन्हें हमने विकास विरोधी का तमगा दिया। कई लोग चिल्लाये कि हिमालय पर ऐसे घाव मत करो। कुछ ने नाकभौं सिकुड़ी की ये सड़क नियमों को ताक पर रख बनाई जा रही है। लेकिन, कौन सुनने वाला था। सबको अपने घर जल्दी पहुंचना था। फिर एक दिन सड़क बन गई। देहरादून से लोगों ने अपनी कार के एक्सलेरेटर पर पाँव रखा, लेकिन नरेंद्रनगर पहुंचते ही उनके उपर पत्थर गिरने लगे। किसी तरह बचते बचाते चंबा तक पहुंचे। चंबा पहुंचे तो पता चला कि एक कार बोल्डर के नीचे दब गई है। लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली दी कि विकास अपनी कीमत मांगता है। अगली बार फिर से कार का एक्सलेरेटर दबाया तो आगराखाल के पास एक पत्थर कार के आगे शीशे पर गिरा और कार चला रहा चालक बदहवास होते होते खाई में जाते जाते बचा। लेकिन उसके पीछे वाला इतना किस्मत वाला नहीं था। उसने तत्काल विकास की कीमत चुका दी। धीरे धीरे दून से अपने घर जल्दी पहुंचने वाले नरेंद्रनगर पहुंचते ही कार के शीशे से आगे देखने के बजाये ऊपर खुरचे गये पहाड़ों पर लटकते बोल्डर देखते हुये टिहरी पहुंचने लगे।

जब कई हादसे हो गये तो फिर टिहरी जल्दी पहुंचने वाले लोगों ने अपनी आदतों में भारी बदलाव किया। मसलन, देहरादून से अपनी कार पर बैठने और एक्सलेरेटर पर पांव रखने से पहले वो अपनी बच्चों को जमकर चूमते, कि क्या पता फिर मुलाकात हो या नहीं।

मेरे घर से कुछ दूरी पर रहने वाला एक फौजी जब अपनी डयूटी कश्मीर जाता तो अपने बच्चों और पत्नी को टाटा बाय बोलकर निकलता। लेकिन इस बार उसे अपने गांव घनसाली अकेले जाना था तो अपने बच्चों और पत्नी से लिपटकर रोया। खैर, मैं तो इतना डरपोक हूं कि एक बार मेरी कार के बोनट पर छोटा से कंकड़ ताछला पर गिरा तो उस दिन के बाद से मैंने टिहरी जाने के लिये अपना पारंपरिक मसूरी का रास्ता पकड़ लिया। हम टिहरी वालों को विकास की बड़ी कीमत देनी आती है। पहले घर खेत डुबा कर दी और अब अपनी सड़क डुबा कर भी दे देंगे। कौन सी बड़ी बात ठहरी।

35 किलोमीटर लंबी सुरंग कब तक बन जाएगी। मुझे देहरादून से शाम को टिहरी झील चाय पीकर लौटना भी है।

2022 के 'दंगल' में किसका होगा 'मंगल'?

कुलदीप राणा आजाद

लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव 2022 का चुनावी रण नजदीक आ गया है। उत्तराखण्ड में जनता अबतक बारी–बारी से भाजपा कांग्रेस को कुर्सी सौंपती आई है, लेकिन इस बार तीसरे विकल्प की छटपटाहट भी दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कि बीते 20 वर्षों में जनता को इन बड़ी पार्टीयों से केवल हताशा और निराशा ही हासिल हुई है। छोटा सा जिला रूद्रप्रयाग राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा चर्चाओं में रहा है। खासतौर पर रूद्रप्रयाग विधान सभा की बात करें तो यहां सियासत का पारा हाई वोल्टेज रहा है। स्थापना काल से लेकर अब तक दिग्गज नेताओं का गढ़ रही रूद्रप्रयाग विधान सभा में भले ही विकास के सवाल आज भी गौंण नजर आते हो लेकिन नेताओं की फेरिस्त दिनोंदिन लम्बी होती जा रही है। आगामी 2022 के चुनावों की अब तकरीबन उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सत्ता रूढ़ दल समेत विपक्षी पार्टी और दावेदारों की एक बड़ी फौज वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह के दांव पेंच आजमाने लगी है। आगामी चुनावों में सभी पार्टियों के प्रबल दावेदारों का परिचय हम आपके सामने रख रहे हैं। पार्टियां किसको टिकट देती है यह तो आने वाले दिनों में तय होगा लेकिन जनता के तराजू में किसका पलड़ा भारी रहता है यह देखना दिलचस्प होगा। आइए! रूद्रप्रयाग की राजनीति में दावेदारों पर एक नजर डालते हैं।

कांग्रेस

मातबर सिंह कण्डारी

लक्ष्मी राणा

प्रदीप थपलियाल

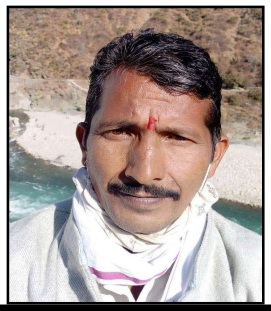

लक्ष्मण रावत

अंकुर रौथाण

भाजपा

भरत सिंह चौधरी

बीर सिंह रावत

विक्रम कंडारी

कमलेश उनियाल

शिव प्रसाद मंमगाई

यूकेडी

मोहित डिमरी

देवेन्द्र चमोली

सरला खण्डूड़ी

आप AAP

प्यार सिंह नेगी

ज्योत सिंह बिष्ट

रूद्रप्रयाग की राजनीति में खास अहमियत रखते हैं मातबर सिंह कण्डारी

मतबर सिंह कण्डारी वैसे तो किसी परिचय के मौहताज नहीं हैं क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन लम्बा है। 25 वर्ष तक विधायक मंत्री और 10 वर्ष प्रमुख रहे चुके कण्डारी पेशे से अध्यापक थे। साल 1964 से 1974 तक बतौर अध्यापक उन्होंने बच्चों को तालिम दी। उसके बाद वे राजनीति के क्षेत्र में उतरे। उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत बनाई की हार जैसा शब्द साढ़े तीन दशकों तक उनके जीवन में कभी आया ही नहीं। वर्ष 1982 में वे पहली बार रूद्रप्रयाग जिले के जखोली से प्रमुख चुने गए और लगातार दो बार प्रमुख रहे। उसके बाद भाजपा के टिकट पर पहली बार वर्ष 1991 में देवप्रयाग विधान सभा सीट से चुनाव लड़ा जीत हासिल की। पुनः 1993 में विधायक चुने गए। उसके बाद 1997 में पर्वतीय विकास मंत्री बने। उस दौर में उत्तराखण्ड का गठन न होने के कारण यह यूपी का हिस्सा था। तब पर्वतीय क्षेत्रों की 19 विधान सभा सीटें हुआ करती थी।

पर्वतीय विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने कई हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट कॉलेजों की स्थापना करवाई, झूला पुलों, सड़कों, आयुर्वेदिक अस्पतालों के साथ ही नव निर्माण हेतु सड़कों की स्वीकृति भी दी। उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पहले विधान सभा चुनाव में 2002 में वे रूद्रप्रयाग विधान सभा से भाजपा से विधायक चुने गए। उसके बाद पुनः 2007 में विधायक बनने के साथ ही सिचाई मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्ड पंम्प और नलकूप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्माण किया।

मातबर सिंह कण्डारी का 1982 से निरंतर अजेय विजयरथ आखिरकार 2012 में थमा जब उन्हीं के साडू भाई हरक सिंह रावत कांग्रेस के टिकट से मातबर कण्डारी को करारी शिकस्त मिली। हालांकि हारने का एक कारण यह भी माना जाता है कि मंत्री बनने के बाद मातबर सिंह कण्डारी का अपनी विधान सभा की ओर अधिक ध्यान न रहना था। जबकि 2017 में भाजपा से उनका टिकट कटा तो उन्होंने भाजपा को ही अलविदा कह दिया। उन्होंने टिकट की चाह में कांग्रेस पार्टी का दामन तो थामा लेकिन तब उन्हें वहां भी टिकट नहीं मिल पाया।

इस बार वे पुनः टिकट की चाह में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। माना जाता कि मातबर सिंह कण्डारी चूल्हे की राजनीति करते हैं अर्थात वे गाँवों में प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत मिलते हैं। यहीं कारण है कि गाँवों में एक बड़ा वोट बैंक भी उनके पक्ष में सदैव रहता है। हालांकि वर्तमान में मातबर सिंह कण्डारी की उम्र उनके राजनीतिक भविष्य में बाधा डाल रही है।

लक्ष्मी राणा ने पिछली बार 15 हजार वोट लेकर कायम किया दबदबा

लक्ष्मी सिंह राणा– पिछली बार के विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस से छः साल के लिए निष्काशित हो रखी लक्ष्मी राणा को एकाएक नामांकन के पूर्व कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। हालांकि लक्ष्मी राणा द्वारा 15 हजार से अधिक वोट लेकर अपना दबदबा भी जरूर कायम किया गया था। क्योंकि इससे पहले रूद्रप्रयाग विधान सभा के चुनावों में हार जीत का फैसला 13 से 15 हजार वोटों के ही बीच होता आया है। लक्ष्मी राणा ने रूद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के बीच खूब पैंठ बनाई थी खासतौर पर अपने गृह क्षेत्र जखोली में उनका काफी दबदबा था। जबकि महिला होने के बाद भी वे एक दबंग नेता की छवि रखती हैं। पिछले विधान सभा चुनावों के परिणाम उनके पक्ष में न आने से वे लम्बे समय तक सीन से गायब रही। यूँ कहें तो जनता से बिल्कुल कट सी गई थी। हालांकि चुनावों से पहले वे एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं।

लस्या पट्टी के पाला कुराली गाँव के जसपाल सिंह राणा के घर 5 जुलाई 1965 को ठाणे (महाराष्ट्र) में जन्मी लक्ष्मी की स्कूली शिक्षा वहीं हुई। पिता की असामायिक मृत्यु के कारण परिवार को वापस गाँव में आना पड़ा और 17 वर्षीय लक्ष्मी के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। गांव में काम करते हुए ग्रामीण समस्याओं और महिलाओं की दुर्दशा ने झकझोरा। इसी से सामजिक क्षेत्र में उतरने तथा महिलाओं और ग्रमीण विकास के लिए कुछ करने के निश्चय को बल मिला। साथ ही अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाया और एम.ए, एलएलबी, किया। चिरबटिया में 'जन विकास संस्थान' के संस्थापन बैशाखी लाल से मिल कर इस दिशा में कार्य आरम्भ किया। महिला व ग्राम विकास के कार्यों को आगे बढत्राते हुए अनेक गतिविधियां संचालित कीं। इसके बाद स्वयं ही 'महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान' का गठन कर महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य व शिक्षा, स्वजल, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं राहत जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इससे उनकी छवि लगातार निखरतली गई और लोकप्रियता बढ़ती गई।

1996 में पंचायती चुनावों की घोषणा होते ही क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों ने उनसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने का आग्रगह किया तो उसमें प्रत्याशी बन गईं और प्रमुख चुन ली गईं। भरपूर उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण लक्ष्मी सिंह राणा ने जखोली विकासखण्ड में कृषि, उद्यानीकरण, पशुपालन, मत्स्य उत्पाद आदि की अनेक परियोजनायें लाकर कृषकों व महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया। सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों पर अनेक पदों पर कार्य करते हुए वे

2014 में जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्रयाग चुनी गई। इसके अलावा जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखण्ड की अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता प्रतिरोद आयोग की सदस्य जैसे पदों पर भी कुशलतापूर्वक कार्य कर चुकी हैं। लक्ष्मी राणा का राजनीतिक अनुभव लम्बा होने के कारण उनकी भी प्रबल दावेदारी हैं किन्तु पिछले कुछ समय से जनता के बीच बनी दूरी को पाटना उनके लिए चुनौतिपूर्ण जरूर रहेगा।

कांग्रेस में प्रदीप थपलियाल की प्रबल दावेदारी

प्रदीप थपलियाल– पिछली बार कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े प्रदीप थपलियाल को भले ही 5 हजार 818 वोटों पर संतोष करना पड़ा हो लेकिन इस बार वे पहले से कई ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। विधायक प्रत्याशी की दावेदारी का संकेत वे प्रदेश आलाकमान के सामने अपने शक्ति प्रदर्शन से कई बार दे चुके हैं। जबकि अपनी विधान सभा क्षेत्र में वे जनता से मिलने का कोई भी मौका नहीं गवा रहे हैं। जखोली से ब्लॉक प्रमुख होने के नाते करीब 108 ग्राम पंचायतों से सीधा उनका सम्पर्क बना हुआ है। वर्ष 2019 में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद जखोली ब्लॉक प्रमुख बने और उसके बाद तुरंत कोविड़–19 संक्रमण होने के कारण लाकडाउन लग गया। इस आपदा के संकट काल में उन्होंने तीन माह तक सरकारी ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को निःशुल्क खाने और रहने की व्यवस्था जिला मुख्यालय में की। जबकि कोविड़ के प्रथम और द्वितीय चरण में जखोली के 108 ग्राम पंचायतों में मास्क, सेनेटाइज, इन्फ्रा थर्मामीटर के साथ साथ प्रत्येक गांव में 3 अक्सोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, क्लॉथमास्क साथ ही आशाओं को पीपी कीट का निःशुल्क वितरण किया। प्रदीप थपलियाल 1993 में गढ़वाल विश्वद्यालय की छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वर्ष 1996 में वे गढ़वाल विवि से चीफ प्रिफेक्ट रहे व 1999 में विश्वविधालय के उप विजेता अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने 2003 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसी दौरान वे वर्ष 2008 तक जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विभिन्न सड़कों के डामरीकरण, विद्यालयों के उच्चीकरण के साथ साथ जखोली तहसील की घोषणा करवाने में अहम योगदान दिया। 2007 से 2014 तक प्रदीप थपलियाल कांग्रेस कमेटी के सदस्य व 2015 से 2017 तक वे रूद्रप्रयाग काग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने अशासकीय विद्यालयों को अनुदान, तिलवाड़ा को नगर पंचायत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2017 में रूद्रप्रयाग विधान सभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। प्रमुख रहते हुए स्वास्थ्य, मनरेगा, कोविड़ के कार्यों के साथ ही जल संवर्द्धन को लेकर 2021 में दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरूस्कार से भी नवाजा गया। वर्मान में भी वे लगातार क्षेत्रीय जनता के बीच बने हुए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा कर टिकट देती है या नहीं यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

जनपद की दोनों विधान सभा पर दावेदारी

लक्ष्मण रावत– छात्र राजनीति से ही जन आन्दोलनों में क्रांतिकारी पृष्ठभूमि के रहे लक्ष्मण सिंह रावत भी कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1990 से 1996 तक क्रमशः छात्र संघ सहसचिव महा सचिव एवं अध्यक्ष के पदों पर चुने जाने के बाद सामाजिक रूप से राजनेतिक क्षेत्र में आने की उत्कंष्ठा उत्पन्न हुई। इसी दौर में वे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के महामंत्री के रूम में कार्य कर चुके हैं। जबकि विश्व विद्यालय में पदाधिकारी रहते हुए छात्र हितों के लिए कई आन्दोलन उनके द्वारा किए गए। इससे पूर्व उत्तराखण्ड आन्दोलन में भी लक्ष्मण रावत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लक्ष्मण रावत साल 2002 में बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) में केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़कर यहां त्रिकोणीय मुकाबले में 4646 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फिर दोबारा वर्ष 2007 में केदारनाथ विधान सभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2008 में कांग्रेस का दामन थामा तो अगले ही वर्ष कांग्रेस हाईकमान द्वारा उन्हें बुद्धिजीवी प्रकोष्ट में प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया जिसकी जिम्मेदारी वे वर्तमान तक निभा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह रावत क्रांतिकारी आन्दोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। राज्य आन्दोलन से लेकर रूद्रप्रयाग में रूद्रप्रयाग जिला आन्दोलन, गुरिल्ला संगठन का आन्दोलन सहभागिता, फर्जी नियुक्यिां के खिलाफ आन्दोलन, राज्य विश्व विद्यालय की स्थापना को लेकर आन्दोलन, रेलवे व चारधाम परियोजना के प्रभावितों के लिए आन्दोलन सहित दर्जनों आन्दोलनों के जरिये उन्होंने जनता के लिए काम किया है। इस बार वे केदारनाथ और रूद्रप्रयाग दोनो विधान सभा से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उन पर भरोसा करती या नहीं यह आने वाले भविष्य के गर्भ में है।

साफ सुथरी छवि के अँकुर रौथाण की युवाओं में पकड़

अंकुर रौथाण– युवाओं में रूद्रप्रयाग विधान सभा से अंकुर रौथाण काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर किए गए कांग्रेस प्रत्याशियों के सर्वे में वे हमेशा युवाओं की पहली पंसद रहे हैं। पूर्व में जिला भेषज संघ में अध्यक्ष और युवा नेता अंकुर रौथाण का नाम टिकट की दौड़ में है। अँकुर रौथाण ने छात्र जीवन से ही अपना राजनीतिक कैरियर आरम्भ कर दिया था।

नवोदित राज्य उत्तराखण्ड में साल 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रवेश लेते ही एन.एस.यू.आई. से जुड़े। इसके बाद वर्ष 2007 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष चुने गए। अंकुर रौथाण ने इस अवधि में युवाओं पर अपनी खासी पकड़ बनाई है। 2008–09 में अंकुर के छोटे भाई अंकित रौथाण गढ़वाल विवि से छात्र संघ अध्यक्ष निवार्चित हुए। वर्ष 2010 में यूथ कांग्रेस के प्रथम चुनाव में रूद्रप्रयाग विधान सभा अध्यक्ष का चुनाव जीते। 2013 में फरवरी में कांग्रेस सरकार द्वारा जिला भेषज व सहकारी विकास समिति के प्रशासक नियुक्त हुए जबकि मई में जिला भेजष एवं सहकारी विकास समिति के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। 2014 में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, 2015 में जनपद रूद्रप्रयाग के राज्य सभा सांसद प्रतिनिधि (राज बब्बर) 2016 में उत्तराखण्ड सरकार में दायित्व सदस्य जैविक उत्पाद परिषद। 2018 में उत्तराखण्ड कांग्रेस सेवादल के प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए। जन सरोकारों के प्रति उनकी निष्ठा और साफ सुथरी सामाजिक छवि के कारण भी उनकी दावेदारी अब सबसे मजबूत नजर आती है। राहुल गांधी के साथ उनकी नजदीकियां और छात्र छात्राओं में उनकी लोकप्रियता चुनाव नतीजों को पलट सकती है। छात्र राजनीति और शिक्षक परिवार से सम्बधित होने का फायदा भी इन्हें मिल सकता है। ठेकेदारी और व्यवसायिकता से दूर अंकुर रौथाण अपने गांव में रहकर सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भागीदारी करते रहते हैं जबकि कांग्रेस पार्टी में पिछले डेढ़ दशक से अलग अलग पदों की जिम्मेदारियां निभाने का लाभ भी उन्हें मिल सकता है।

अब बात कर लेते हैं भाजपा की। वर्ष 2017 के विधान सभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी को ऐतिहासिक जीत मिली है। करीब 29 हजार से अधिक वोट लेकर भरत सिंह चौधरी ने विधायक पद की कमान सम्भाली। इस वक्त भाजपा के लिए उसी पुरानी जीत को बरकरार रखना चुनौती है। जबकि सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान द्वारा दो आंतरिक सर्वे किए जा चुके हैं जिनमें रूद्रप्रयाग विधान सभा से चार लोगों के नाम सर्वे रिपोर्ट में शामिल हैं। समझा जा सकता है कि भरत सिंह चौधरी द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद भी भाजपा के कई अन्य नेता भी टिकट की दौड़ में नजर आ रहे हैं ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के भीतर भी भारी द्वंद चल रहा है। पहले विधायक भरत सिंह चौधरी पर एक नजर डालते हैं उसके बाद अन्य दावेदारों की बात करते हैं–

आसान नहीं होगा ऐतिहासिक जीत दौहराना

भरत सिंह चौधरी– वर्तमान विधायक होने और पिछली बार मिले लोगों के अपार जन समर्थन के साथ साथ लम्बा राजनीति अनुभव भरत सिंह चौधरी को मजबूत स्थिति दिखा रहा है। भरत सिंह चौधरी का सामाजिक संर्घष बहुत लम्बा रहा है। कई बार चुनावों में पराजित होने के बाद भी समाज सेवा में जुटे रहने और चुनावों में भी लगातार भागीदारी करते रहने वाले भरत सिंह चौधरी सबसे पहले 1985 में नगरासू साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष और 1988 में प्रधान चुने जाने के बाद 1989 में जिला पंचायत के सदस्य, 1989 में जनता दल की ओर से विधान सभा का चुनाव लड़ा, 1996 व 2002 में कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार विधान सभा सदस्य का चुनाव लड़ा। 2003 में देवभूमि रचनात्मक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति का गठन कर लोगों को स्वरोजगार हेतु तैयार करने, 2007 में एनसीपी के टिकट पर तथा 2012 में निर्दलीय रूप में पुनः चुनाव लड़ा। 2008 में हरियाली सर्वजन कल्याण समिति के अध्यक्ष बने। रूद्रप्रयाग में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मंच की स्थापना कर मानवाधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकारों के लिए कार्य किये। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में भरत सिंह चौधरी को भाजपा का टिकट मिला और वे भारी बहुमत से चुनाव जीत कर विधान सभा पहुँचे। अब करीब साढ़े चार वर्ष का उनका कार्यकाल बीत चुका है जिसमें उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अंचलों को सड़कों से जोड़ने के कार्य किये। पूरे उत्तराखण्ड में कई गाँवों व तोक को सड़क मार्ग से जोड़ने में बाधा बना कोर नेटवर्क को तोड़ने में भरत चौधरी की बड़ी भूमिका रही फलस्वरूप रूद्रप्रयाग विधान सभा में करीब 119 सड़कें स्वीकृत हुई। जबकि जिला प्लान की सड़के राज्य योजना में और राज्य योजना की सड़कों को पीएमजीएसवाई में डलवाकर सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का श्रेय भी भरत सिंह चौधरी को ही जाता है। 12 सड़कों का निर्माण वे खुद विधायक निधि से कर चुके हैं। 57 ग्राम सभाओं को सीएसआर फंड से तीन हजार सौलर लाईट, 108 ग्राम सभाओं की महिला मंगल दलों 1–1 लाख का सामान, आँगनबाड़ियो को गैस चूल्हा व सिलेण्डर, युवक मंगलदलों को स्पोर्ट्स किट दे चुके हैं जबकि अपनी विधायक निधि का वे 52 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर चुके हैं। जिला अस्पताल को 22 लाख की लइप्रोस्कोपी मशीन व 28 डॉक्टरों की तैनाती भी वे करवा चुके हैं। जबकि कोविड काल में करीब 40 लाख रूपये उनके द्वारा विधायक निधि से दिये गए।

हालांकि इस बीच उन पर कई तरह के आरोप भी लगाये जाते रहे हैं। जबकि कई बार जनता के बीच उनके बड़बोलापन और गुस्सेल मिजाज के कारण उनकी किरकिरी भी हुई है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हर क्षेत्र से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को विश्वास में लेकर समस्याओं के निपटारे की दिशा में कार्य करना विधायक के कुशल राजनीति को सामने ला सकता है और इसी से राजनीति में उनका रास्ता सुगम भी बन सकता है।

बीर सिंह रावत संघ में रखते हैं पकड़

भाजपा में टिकट के लिए खुलकर सामने आने वालों में बीर सिंह रावत का नाम टिकट की दावेदारी में सबसे पहले आता है। जबकि सोशल मीडिया में हुए एक सर्वे में भी बीर सिंह रावत सबसे आगे रहे हैं। शुरूआत से ही भाजपा संघ से जुडे होने के साथ बीर सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में कई दायित्व भी निभा चुके हैं। साल 1989 में भाजपा के सम्पर्क में आए और उसके बाद पार्टी के लिए काम करने लगे। पहली बार 1997 में कण्डाली वार्ड से भाजपा के समर्थन पर जिला पंचायत का चुनाव लडा। उस वक्त 45 वोट से पीछे रह गए। उसके बाद 2003 में कुमड़ी वार्ड से क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा तो भारी मतों से विजय हासिल की और विरोधियों की जमानत जब्त कर दी।

वर्ष 2003 में भाजपा की ओर से जखोली ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा और अपने लोगों की भीतरीघात की वजह से 1 वोट से हार का समना करना पड़ा। वर्ष 2005–06 में लघु सिंचाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय में 4 दिनों तक भूखहड़ताल पर बैठे और शासन प्रशासन को हिला दिया। बाद में 5वें दिन तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष मातबर सिंह कण्डारी व तत्कालीन जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई के खिलाफ तुंरत जांच कर कार्यवाही के आश्वासन पर भूखहड़ताल तुड़वाई।

वर्ष 2007 में भाजपा से रूद्रप्रयाग विधान सभा से टिकट की दावेदारी की किन्तु टिकट न मिलने से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और लगभग 4 हजार वोट प्राप्त किए। जबकि उस वक्त बीर सिंह रावत के क्षेत्र से ही करीब छः अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे। वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री भुवनचंन्द्र खण्डूरी और संगठन प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और कई भाजपा नेता व पदाधिकारियों की अगुवाई में पुनः भाजपा में वापसी हुई। इसी वर्ष बीर सिंह रावत की पत्नी बिमला रावत ने निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और सबकी जमान जब्ज कर भारी मतों से विजय हासिल की। जो बाद में भाजपा में शामिल हुई। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला पंचायत सदस्य के लिए समर्थन था किन्तु अपने ही लोगों की भितरीघात और षड़यंत्र के कारण फिर से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा संगठन में बीर सिंह रावत कई दायित्य निभा चुके हैं वर्ष 1991–94 में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारणी में सदस्य, वर्ष 2004 में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी, 2009 में विधानसभा चुनावों में प्रचार करने गए। 2009 में विकासनगर के उपचुनाव में प्रचार प्रभारी आदि दायित्व निभा चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं । भाजपा हाईकमान बीर सिंह रावत पर भरोसा करता है या नहीं यह देखना होगा।

विक्रम कंडारी का नाम भी अहम

आगामी 2022 के विधान सभा चुनावों में भाजपा से विक्रम कंडारी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी दावेदारी पिछली बार भी किन्तु पिछली बार टिकट न मिलने के कारण उन्होंने संगठन और भाजपा को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। विक्रम कंडारी एक ऐसा नाम है जिनका ग्राम स्तर के चुनावों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधान सभा और लोक सभा के चुनावों की गणित को सटीक बिठाने में अहम भूमिका रहती है।

दरअसल विक्रम कण्डारी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हो गए थे। साल 1994 में उत्तराखण्ड आन्दोलन में छात्र संगठनों के साथ आन्दोलन को मुकाम तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 1997 में रूद्रप्रयाग को जिला बनाने का आन्दोलन आरम्भ हुआ तो यहाँ भी पुरजोर तरीके से जनपद निर्माण को लेकर मुखर हुए और मंजिल हासिल की। वर्ष 2003 व 2008 में अपने गाँव गीड़–भुतेर से दो बार प्रधान चुने गए। वर्ष 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी से विधान सभा का चुनाव भी लड़ा और 42 सौ वोटों के साथ चौथे नम्बर पर रहे।

2008 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसी दौर में उन्हें पंचायत प्रकोष्ठ का जिला संयोजक का दायित्व भी मिला। इस दौरान वे लगातार लोगों के बीच न केवल सुख दुःख में बने हुए थे बल्कि क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के निराकरण के प्रति भी वे लगातार कार्य करते आ रहे थे। वर्ष 2009 में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी विक्रम कण्डारी को सौंपी गई। 2011 में भाजपा जिला महामंत्री बने और बेहतर कार्यकाल रहा। 2012 के विधान सभा चुनावों में विधान सभा प्रभारी की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। 2014 के लोक सभा चुनावों में बूथ सत्यापन के कार्य में कंडारी की भूमिका अग्रणी रही। इसके बाद उन्हें तीन वर्ष संघ और भाजपा का समन्वयक का दायित्व दिया गया। साल 2018 में संघ का समन्वयक व अगले वर्ष दोबारा पार्टी ने महामंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसका निर्वहन वे वर्तमान में भी कर रहे हैं।

2022 में विक्रम सिंह कण्डारी द्वारा पार्टी से विधायक के टिकट की मांग की जा रही है और दावेदारों की सूची में उनका नाम भी अहम है। उनके पूरे राजनीतिक पृष्टभूमि पर नजर डाली जाय तो ग्राम प्रधान से लेकर लोक सभा तक के चुनावों का उन्हें अच्छा खास अनुभव है। हालांकि 2022 के चुनावी मैदान में भाजपा किस प्रत्याशी पर भरोसा जताती है यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

UKD
उत्तराखंड क्रांति दल

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में जिस उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का बड़ा योगदान था राज्य बनने के बाद आज तक उसे कभी सत्ता नसीब नहीं हो पाई है। कुछ सीटों पर जनता ने भरोसा किया भी तो यूकेड़ी ने जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया जिस कारण आज पार्टी हाशिए पर है हालांकि इस बार काफी ऊर्जावान युवा इस दल से जुड़ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी यूकेड़ी को तीसरे बिकल्प के तौर पर लोग देखते हैं लेकिन यहां नेताओं और संसाधनों दोनों का भारी अभाव है। रूद्रप्रयाग विधान सभा में मुख्यतः तीन दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। दावेदारों पर एक नजर–

सामाजिक सरोकारों के लिए लड़ने वाले मोहित यूकेडी में भर रहे ऊर्जा

समाज के लिए कुछ करने और सिस्टम की खामियों को खत्म कर नया बदलाव लाने का जूनून मोहित डिमरी के दिल में बचपन से ही था। इसलिए उन्होंने कलम की ताकत हथियार बनाने का फैसला किया और वर्ष 2007 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पर्दापण किया। दैनिक राष्ट्रीय सहारा अखबार से पहले जनपद रूद्रप्रयाग की छोटी–बड़ी समस्याओं के साथ भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। व्यवस्था की खामियों को उजागर करते रहे। 2010 में टीवी चैनल सहारा समय भी ज्वाइन किया और अखबर के साथ साथ चैनल के माध्यम से भी जन सरोकारों की पत्रकारिता करते रहे। 2012 की उखीमठ त्रासदी हो या फिर 2013 की केदारनाथ आपदा इन दोनों आपदाओं में मोहित की राहत बचाव के कार्यों की रिपोर्टिंग से लेकर प्रभावित केदारघाटी की समस्याओं और उनके निदान के लिए लगातार ग्राउण्ड जीरों की रिपोर्टिंग की। इन आपदाओं में बेहतर रिपोर्टिंग करने के लिए मोहित को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिला दीक्षित द्वारा सम्मानित भी किया गया। 2018 में स्थाई राजधानी गैरसैंण संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाये जाने के उपरान्त राज्य भर में व्यापक आन्दोलन किया गया। 2019 में रूद्रप्रयाग में जन अधिकार मंच का गठन कर न केवल लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं की लड़ाई लड़ी बल्कि चार धाम परियोजना प्रभावित व्यापारियों और भवन स्वामियों की मुआवजें की लड़ाई एक वर्ष तक लड़ी जिसका परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में व्यापारियों और भवन स्वामियों को मुआवजा मिला। वहीं जखोली के बुढ़ना गांव की दलित राखी देवी को मकान बनाकर भी दिया।

कोरोना काल में मोहित डिमरी द्वारा जगह जगह फंसे प्रवासियों को सकुशल घर पहुँचाने की लड़ाई में बेहतर कार्य किया गया जिसका लाभ हजारों को प्रवासियों को मिला, जबकि कोरोना से बचाव की सामग्री भी उनके द्वारा लगातार गाँवों में वितरित की गई।

उत्तराखण्ड को बेहतर दिशा और दशा देने भावना को लेकर उन्होंने उत्तराखण्ड क्रांति दल में शामिल हुए और दल के साथ सैकड़ों युवाओं को जोड़ रहे हैं। जबकि इससे पहले पहली बार उन्होंने 2019 में सौंरा जवाड़ी सीट पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें सम्मानजनक मत हासिल हुए। इस सीट पर मोहित की माता आशा डिमरी दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। युवाओं में खासी पकड़ रखने वाले मोहित डिमरी को यूकेड़ी से इन्हें टिकट मिलता है तो समीकरण बदल सकते हैं।

देवेन्द्र चमोली भी यूकेड़ी के अहम चेहरे

वर्तमान में यूकेड़ी में केन्द्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सम्भाल रहे देवेन्द्र चमोली मूल से पत्रकार हैं किन्तु छात्र जीवन से ही उनकी सक्रियता राजनीति में रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता के रूप में पहचान बनाने के बाद उक्राराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। 1994 में पृथक राज्य की लड़ाई में पौड़ी कमीश्नरी घेराव, मुजफ्फरनगर कांड, श्रीनगर में ऐतिहासिक से श्रीयंत्र टापू आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के साथ यातनाएं झेली। क्षेत्रीय विचारधार से प्रभावित देवेन्द्र चमोली ने वर्ष 1999 में उत्तराखण्ड क्रांति दल (उक्रांद) में सक्रिए हुए।

जनपद रूद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष सहित संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में उक्रांद के केन्द्रीय प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे चमोली विगत 22 वर्षों से जनपद रूद्रप्रयाग में सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जबकि पत्रकारिता के जरिए क्षेत्र की समस्याओं को भी वे निरंतर उठाते आ रहे हैं।

सरला खण्डूड़ी भी टिकट की रेस में

भारतीय जनता पार्टी में लम्बे समय पर रहने के बाद पार्टी द्वारा उपेक्षा का शिकार हुई सरला खण्डूड़ी ने हाल ही यूकेडी का दामन थामा है और पार्टी से अब टिकट की दावेदारी भी कर रही हैं। सरला खण्डूडी ने 1994 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के विभिन्न काक्रमों व चुनावों में सक्रिय भागीदारी निभाई। वह राष्ट्रीय सेवासमिति में स्वंय सेविका के रूप में सक्रिय रही हैं व संघ के विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण भागीदारी का निर्वहन कर चुकी हैं।

भाजपा में रूद्रप्रयाग जिले में महिला मोर्चा में जिला कोषाध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य, महिला मोर्चा की चमोली जिला प्रभारी के रूप में विभिन्न मंडलों के गठन जिला कार्यकारिणी के गठन बैठकों व सम्मेलनों में महत्पपूर्ण भागीदारी, भाजपा रूद्रप्रयाग जिला कार्यकारणी में में जिला उपाध्यक्ष, उखीमठ मंडल प्रभारी के रूप में विभिन्न न्याय पंचायतों में बी0एल0ए0 इत्यादिकी नियुक्ति, सत्यापन व भिन्न गांवों में व्यापक जन सम्पर्क, पार्टी द्वारा महिला मोर्चा में चमोली एवं रूद्रप्रयाग जनपद के लिए विभाग सहयोजिका का दायित्व का निर्वहन,महिला मोर्चा में पुरोला जनपद प्रभारी के रूप में विभिन्न कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा की गढ़वाल संयोजक के दायित्वों का निर्वहन करने के साथ 2012 विधान सभा चुनावों में रूद्रप्रयाग और श्रीगन में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके आलावा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री के साथ ही महिला मोर्चा में प्रदेश महामन्त्री के पद पर कार्य कर चुकी हैं।

इसके अलावा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सरला खण्डूडी की पार्टी पर लगातार उपेक्षा की गई तो उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर उक्रांद में शामिल हो गई। अब यहां भी वे टिकट की दावेदारी कर रही हैं। ❑❑❑

जन सेवा से भाजपा को मजबूत करने वाले स्तम्भ कमलेश उनियाल

वर्तमान पारिस्थितियों में लोगों की सोच और समझ में राजनीति के असल मायने दौलत, सौहरत व पद प्रतिष्ठा कमाने मात्र की रह गई हो लेकिन इस राजनीति के गंदलाते घालमेल में कुछ लोग हैं जो कमल की तरह खिलकर राजनीति को पेशा नही जन सेवा समझते हैं और उसी से अनुरूप काम करते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं कमलेश उनियाल, जिन्होंने छात्र जीवन से ही अभावों, समस्याग्रस्त लोगों, शोषित पीड़ितों की हर संभव सहायता कर जन सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं और आज भी उसी पर कार्य कर रहे हैं।

रूद्रप्रयाग जनपद के जखोली लस्यापट्टी के देवल गांव में 1 दिसम्बर 1975 को श्री पीतांबर उनियाल और शांति उनियाल के घर जन्मे कमलेश उनियाल के अंदर पढ़ले लिखने के साथ साथ समाज के प्रति कुछ कर दिखाने का जुझारूपन था। उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड युवा संगठन बनाकर राज्य निर्माण के लिए युवाओं को एकत्रित कर आन्दोलन को सफलता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तराखंड आंदोलन में दिल्ली जाते समय रामपुर तिराहे पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल भी हुए। छात्र जीवन से ही नेतृत्व कर समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से राजनीति में सक्रिय हुए। सन् 1996 में ऋषिकेश राजकीय महाविद्यालय से यू0आर0 रहे। वर्ष 1997 में महा सचिव राजकीय महाविद्यालय, ऋषिकेश में चुनाव लड़ा। साल 1998 में अखिल भारत विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष चुने गए। जबकि इस दौर में ट्रांसपोर्ट यूनियन में जुड़कर मोटर मालिक व चालकों की समस्याओं की लड़ाई में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई।

उच्च शिक्षा ऋषिकेश देहरादून प्राप्त करने के कारण ऋषिकेश और देहरादून जैसे मैदानी क्षेत्रों में राजनीति में सक्रिय हुए कमलेश उनियाल सन् 1999 से 2002 तक डोईवाला ग्रामीण मण्डल से अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उस दौरान कमलेश उनियाल ने स्थानीय ग्रामीणों के विद्युत संयोजन, ग्रामीण मार्ग निर्माण के लिए आंदोलन कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य किया। सन् 2005 से 2008 तक प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा में रहकर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा से युवाओं को जोड़ने का बड़ा कार्य किया। 2009 से 2011 तक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा देहरादून रहकर तत्कालीन भाजपा सरकार से विस्थापन व बाढ़ नियंत्रण के लिए आम जनमानस के लिए कार्य किया। जबकि इस दौरान उन्होंने व्यापक स्तर पर रक्तदान शिविर लगवाएं, कई प्राइवेट व निजी संस्थाओं से हेल्थ चेकअप कैंप लगाएं। साथ ही कई लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलाने में पूर्ण सहयोग किया। सन् 2012 से 2016 तक प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहते हुए पार्टी के लिए बेहतर कार्य किए।

चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर माइक्रोमैनेजमेंट कर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। वर्ष 2017 दिसम्बर से 2018 नवम्बर तक मिशन 2019 विस्तारक प्रमुख प्रभारी जिला, रूद्रप्रयाग रहते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ–साथ जनपद रुद्रप्रयाग के लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। सन् 2018 से जुलाई 2019 मक मिशन 2019 सह–लोकसभा विस्तारक, प्रभारी, हरिद्वार (विशेष कार्य –विधानसभा धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार ग्रामीण, रानीपुर) मंडल शक्ति केंद्र भूत स्तर पर पन्ना प्रमुख की रचना कर हरिद्वार विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी डॉ रमेश पोखरियाल निशंक का ऐतिहासिक जीत दिलाने का सहयोग रहा। इसके उपरांत

केंद्र व प्रदेश संगठन ने वर्तमान में प्रदेश संगठन में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भाजपा का दायित्व निभा रहे है।

इस कार्यकाल के दौरान कमलेश उनियाल ने सरकार की उपलब्धियों को मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में जन–जन तक पहुंचाने का कार्य किया तथा साथी अपने गृह जनपद रुद्रप्रयाग में आज भी लगातार प्रवास के दौरान स्थानीय जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनका निवारण संबंधित अधिकारी व विभागीय मंत्रियों के माध्यम से करवा रहे हैं। राजनीति रूप से भले ही कमलेश उनियाल अपने गृह जनपद से बाहर लम्बे समय तक रहे हो लेकिन देहरादून में रहकर उन्होंने कई लोगों के कार्य निस्वार्थ भाव से किए हैं और वर्तमान में भी रुद्रप्रयाग जनपद की जनता के मन व मस्तिष्क में अपनी सकारात्मक पहचान बनाई है। कमलेश उनियाल के लम्बे कार्यकाल और संघर्ष के बार में जब भी पूछा जाता है तो उनका जवाब होता है कि 'मैं आज जो भी हूं भारतीय जनता पार्टी संगठन की देन हूँ। क्योंकि उनके छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व भारतीय जनता पार्टी के 24 वर्ष के कालखंड में संगठन से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए आज विश्व के इतनी बड़ी राजनीतिक संगठन ने एक आम व्यक्ति को न केवल प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी भाजपा ने बनाया है बल्कि जन सेवा का अवसर भी प्रदान किया। इसके लिए मैं पार्टी का सदैव ऋणी रहूंगा।

कमलेश उनियाल की इसी जीवटता और सौम्य व्यवहार के साथ जन सेवा की भावना के कारण आज लोग उनके प्रति अपना प्रेम स्नेह भरपूर देते हैं। जहाँ–जहाँ वे पहुँचते हैं लोग ढोल नगाढ़ों के साथ पहले ही उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। जनता का इतना समर्थन वास्तव में उनके 24 वर्षों के संघर्ष को बयां करता है।

रूद्रप्रयाग जिले को लेकर भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि इस जनपद का मूल निवासी होने के नाते रूद्रप्रयाग से भावनात्मक जुड़ाव है। कहा मैं छोटा था तो मेरी मां जखोली ब्लॉक के बजीरा प्राइमरी स्कूल में शिक्षाका थी। सड़क न होने के कारण गांव देवल से पैदल ही मां के साथ पढ़ने के लिए जाया करते थे। पलायन को लेकर पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा पहाड़ का युवा आज रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं जिन्हें उत्तराखण्ड के भीतर ही रोजगार देकर यहां रोकने के प्रति संवेदनशील है। इसलिए सरकार भी पहाड़ों में रोजगार स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है लेकिन आज मैंने देखा है कि पूर्व की भांति युवाओं की सोच में पहले से ज्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले युवा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी का विचार व लक्ष्य बनाते थे, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बड़े–बड़े पैकेज के साथ प्राइवेट नौकरी करना पसंद करता थे। कुछ युवा डॉक्टर, वकील बनकर सेल्फीएम्पलाई बनना चाहती थे किंतु आज के परिपेक्ष के हिसाब से हमारे युवाओं की सोच कहीं ना कहीं बदल रही है आज के ज्यादातर युवा स्वरोजगार को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और यह एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर सभी युवा नौकरी करना चाहेंगे तो चाह कर भी इतनी नौकरियां नहीं हो सकती, इसलिए युवा चाह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने और

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वरोजगार के लिए ही अपने मन की बात में युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं इसी सोच के हिसाब से में यह मान रहा हूं कि जनपद रुद्रप्रयाग के युवाओं के लिए 'तकनीकी शिक्षा', 'टूरिज्मएडवेंचर की शिक्षा' की वर्कशॉप सरकार के माध्यम से या किसी संस्था द्वारा या स्वयं अपने माध्यम से करवाने का एक संकल्प मेरे द्वारा लिया गया है। क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग में ट्रैकिंग,पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही युवाओं को अपने कैरियर चुनने हेतु जनपद व ब्लॉक स्तर पर 'विचार बैंक की स्थापना करनी है जिसका कार्य मेरी व्यक्तिगत व मेरे साथ लगी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कमलेश उनियाल द्वारा पंचायत स्तर पर 'एग्रीकल्चर वर्कशॉप' लगाने का भी संकल्प लिया है ताकि जनपद रुद्रप्रयाग की खेती की जमीन की जांच कराकर सही फसल व सब्जियों के उत्पादन के संबंध में जानकारी दी जाए। केंद्र सरकार की योजना किसानों की आमदनी तीनगुनी करने की ताकि यहां का युवा व किसान उसकी खेती करें व अपने उत्पादन को बेचकर सही मूल्य प्राप्त करें इसके अलावा मेरे स्वयं के द्वारा समस्या सुझाव ऐप भी बनाया गया है जिसमें हमारे पास अभी तक विधानसभा रुद्रप्रयाग व केदारनाथ से व्यक्तिगत 885 समस्याएं लोगों द्वारा दी गई जिसमें से 418 समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी को अवगत करा कर मेरी व्यक्तिगत टीम द्वारा निवारण किया गया है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर मेरे द्वारा वॉलिंटियर बनाए गए हैं जो स्थानीय समस्याओं को बताते हैं तथा हम उनके निवारण हेतु संबंधित मंत्री व संबंधित सरकार अधिकारी द्वारा निस्तारण करने का प्रयास करते हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड

राज्य सैक्टर की योजनायें–

1. मधुमक्खी पालन योजना के तहत 1 है0 पर 4 बाक्स, रू. 350 प्रति बॉक्स सहायता।
2. उद्यानों की घेरबाड़ की योजना पर 50प्रतिशत राज सहायता, अनुदान 1 लाख प्रति है0।
3. मशरूम उत्पादन एवं विपण हेतु 50 प्रतिशत सहायता।
4. बाजार हस्तक्षेप योजना में समर्थन मूल्य पर क्रय की व्यवस्था।
5. फसल बीमा योजना में प्रीमियम पर 50 प्रतिशत सहायता।
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचचित जनजाति क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी एवं मसाला उत्पादन योजना के लिए सहायता।
7. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औद्योनिक विकास हेतु 50 प्रतिशत सहायता।

बागानों के जीर्णेद्धार की योजना हेतु सहायता।

10. बोरबैल स्थापना योजना के अन्तर्गत रू0 1 लाख प्रति इकाई स्थापना हेतु सहायता।
11. पॉलीहाउस के पालीथीन बदलाव योजना के अन्तर्गत 50 वर्गमीटर का 75 प्रतिशत अनुदान।
12. पावर मशीन (ट्रैक्टर) योजना में ट्रैक्टर खरीद हेतु सहायता।
13. पौधरोपण योजना के तहत निःशुल्क फलपौध वितरण सहायता।
14. मसाला खेती योजना मसाला फसलों की खेती के लिए सहायता।
15. वर्मीकम्पोस्ट योजना में वर्मीकम्पोस्ट पिट निर्माण हेतु सहायता
16. एण्टी हेलनेट योजना के तहत फसलों को ओलावृष्टि से बचाव हेतु एण्टी हेलनेट हेतु सहायता।
17. उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए योजना में रू0 50,000 प्रति है0 का 75 प्रतिशत सहायता।
18. राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत निजी क्षेत्र के उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु परियोजना।
19. मसाला मिर्च प्रोत्साहन योजना के तहत कृषकों को रू. 700 प्रति कु0 प्रोत्साहन राशि।
20. वर्मी कम्पोस्ट इकाई योजना में रू0 33,000 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत सहायता।
21. मिशन एम्पल योजना में रू0 12 लाख प्रति एकड़ 50

जिला सैक्टर की योजनायें–

1. उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन/पौधालय विकास योजना के तहत बीच के परिवहन पर शतप्रतिशत राजसहायता। नये उद्यानों की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत सहायता। कीटव्याधिनाशक रसायनों की वितरण एवं कुरमुला कीट नियन्त्रण हेतु 60 सहायता। औद्यानिक औजार वितरण हेतु 50 प्रतिशत सहायता।
2. फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण योजना में 50 प्रतिशत सहायता।
3. प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेंत्रों में औद्यानिक विकास हेतु 50 प्रतिशत सहायता।

केन्द्र योजना– 1. बागवानी मिशन

1. पौधशाला की स्थापना योजना में हाईटेक पौधशाला स्थापना हेतु रू0 25 लाख प्रति है0 (राजकीय हेतु 100 प्रतिशत व व्यक्तिगत 40 प्रतिशत), छोटी पौधशाला हेतु रू0 15 लाख प्रति है0 (राज 100 प्रतिशत व व्यक्तिगत 40 प्रतिशत)
2. सब्जी एवं मसाला बीज उत्पादन राजकीय हेतु 100 प्रतिशत व व्यक्तिगत 40 प्रतिशत, ओपन पॉलीनेटिड फसल पर रू. 35,000 प्रति है0 व हाईब्रिड बीज रू0 1.50 लाख प्रति है0।
3. नए उद्यानों की स्थापना हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत सहायता। सब्जी क्षेत्र विस्तार हेतु 50 प्रतिशत मसाला क्षेत्र विस्तार हेतु 40 प्रतिशत सहायता।
4. पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार हेतु 50 प्रतिशत सहायता।

योगेन्द्र सिंह चौधरी

जिला उद्यान अधिकारी रूद्रप्रयाग

योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग रूद्रप्राग से संपर्क कर सभी योजनाओं का लाभ उठाएं।

समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

आईए! राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभायें। हमारी जिम्मेदारी राष्ट्र को नई ऊँचाईयां प्रदान करती है।

लक्ष्मण रावत

बुद्धिजीवी प्रकोष्ट
प्रदेश महासचिव
एवं वरिष्ठ कांग्रेसी
आन्दोलनकारी नेता

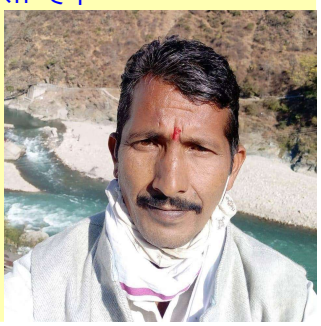

समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन व जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

अजय थपलियाल

सहायक अभियंता
प्रांतीय लोक निर्माण विभाग

आईए इस स्वतंत्रता दिवस संकल्प लें! राष्ट्र के निर्माण में अपनी जिम्मेदारियों का न पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें!

समस्त प्रदेश वासियों को सम्पूर्ण जल संस्थान परिवार रूद्रप्रयाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

जल ही जीवन है- जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है।

जल सस्थान जनपद रूद्रप्रयाग

इं. संजय सिंह
अधिशासी अभियंता

केदारघाटी का चहुँमुखी विकास मेरी प्राथमिकताः तिवाड़ी

केदारघाटी में जब भी संघर्षों का जिक्र आता है तो युवा नेता के रूप में सुमंत तिवाड़ी का नाम सबसे शीर्ष पर नजर आता हैं। क्योंकि सुमंत तिवाड़ी एक ऐसा ऊर्जावान नेता हैं जिन्होंने जनता की समस्याओं के निदान के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार आन्दोलन किए हैं। केदारनाथ त्रासदी के बाद जीवन को पटरी पर लाने की लड़ाई हो या फिर क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल की समस्याओं के निराकरण की बात रही हो। हर मोर्चे पर सुमंत तिवाड़ी ने जनता के बीच रहकर जनता के कंधो से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। यहीं कारण है कि जनता का प्यार–स्नेह और आशीर्वाद भी उन्हें मिलता रहा है।

सुमंत तिवाड़ी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में साल 1999 से वर्ष 2004 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एन एस वाई) के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने छात्र हितों के लिए अनेक कार्य किए। सुमंत तिवाड़ी का पहले से ही समाज के भीतर परिवर्तन लाने के साथ लोगों की समस्याओं के लिए जूझना और उनका निराकरण करना एक शौक जैस रहा है। इसी खूबी के कारण 2004 से 2006 तक वे गढ़वाल विश्वविद्यालय में चीफ प्रीफैक्ट चुने गए। इसके बाद वे यूथ कांग्रेस में सक्रिय हो गए।

वर्ष 2014 में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव व 2015 में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मिली। वर्ष 2014 में फेंगू वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए जबकि ब्लॉक प्रमुख दो वोट से हार गए। इस दौरान सुमंत तिवाड़ी ने वर्ष 2013 की भीषण प्रलयकारी बाढ़ से प्रभावित हुई समूची केदारघाटी के आपदाग्रस्त गाँवों की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाई। आपदा के कई वर्षों बाद तक वे प्रभावित ग्रामीणों की दिनचर्या पटरी पर लाने के लिए आन्दोलन करते रहे। चन्द्रपुरी, विजयनगर, कालीमठ आदि कई जगहों पर झूला पुलों के निर्माण को लेकर भी उन्होंने कई अन्दोलन किये। जबकि आपदा में क्षतिग्रस्त हुए सम्पर्क मागों को ठीक करने को लेकर जहाँ वे निरंतर सक्रिय रहे वहीं आपदा में क्षतिग्रस्त आवासीय व व्यावसायिक भवनों के मुआवजे को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाजें उठाई।

वर्ष 2015 में एल एण्ड टी कम्पनी द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरी से हटाने के बाद सुमंत तिवाड़ी ने कम्पनी द्वारा हटाये गए बेरोजगार युवाओं की नौकरी बहाल करने को लेकर बड़ा आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप कई युवाओं की कम्पनी द्वारा बहाली भी की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र की एक दर्जन से अधिक विद्यालयों में अध्यापकों के कई पद सृजित करवाये। जबकि महिलाओं और युवक मंगलदलों को वे हमेशा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते रहे।

साल 2019 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए आई सी सी) के सदस्य की जिम्मेदारी मिली। जबकि इसी वर्ष जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने पाँच दिनों तक भूख हड़ताल की। जिला अधिकारी के लिखित आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया था जिसके बाद काफी हद तक जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ढर्रे पर लौट आई थी, जिसका लाभ पूरे जिले को मिला है।

2019 में जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जिला योजना के माध्यम से एक दर्जन से अधिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण किया। वहीं चाइल्ड फंड से भी उन्होंने एक दर्जन से अधिक विद्यालयों में कार्य करवायें। क्षेत्र में पेयजल को लेकर भी उन्होंने कई योजनाओं का निर्माण कर ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात दिलाई है।

आम तौर पर राजनेताओं की आदत झूठे वादे करने और चुनाव जितवाने के बाद सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन सुमंत तिवाड़ी एक ऐसा नेता हैं जो भी उनके पास मदद के लिए आते हैं वे उन्हें न भरोसा

दिलाते हैं और न वादा करते हैं बल्कि तत्काल उनकी मदद के लिए कार्य आरम्भ कर देते हैं। उन्होंने सैकड़ों बालिकाओं की शादियों में बड़ी मात्रा में आर्थिक रूप से मदद की है जबकि सैकड़ों मरीजों को ईलाज के लिए आर्थिक मदद की है। बावजूद वे अपने द्वारा किए गए नेकी के कार्यों को कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं, ऐसे में मामलों में सुमंत तिवाड़ी एक ऐसा नेता हैं जो प्रचार–प्रसार से बहुत दूर रहते हैं। 130 से अधिक कीर्तन मंडलियों को कीर्तन का सामान, युवक मंगल दलों को स्पोर्ट्स का सामान दे चुके हैं। पिछले कोरोना काल में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाहर से आने वाले प्रवासियों को रूद्रप्रयाग गुलाबराय मैदान में करीब 15 दिनों तक निःशुल्क लंच की व्यवस्था की, जिसका लाभ हजारों प्रवासियों को मिला। जबकि इसके बाद गांव गांव में कोरोना से बचाव की सामग्री का वितरण भी वे लगातार करते रहे। युवाओं को रोजगार देने को लेकर वे हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। रेलवे के प्रोजेक्ट कार्य कर रही कम्पनियों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने को लेकर भी वे लगातार कम्पनियों पर दबाव बना रहे हैं।

लम्बे समय से कांग्रेस में रहे सुमंत तिवाड़ी ने इस वर्ष आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और केदारनाथ विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आप पार्टी कर्नल अजय कोठियान के नेतृत्व में मिशन 2022 फतह के लिए तैयार है और कर्नल अजय कोठियाल द्वारा जिस तरह से उत्तराखण्ड के लिए काम किया है, खास तौर पर यूथ फॉउण्डेशन के जरिए युवाओं को मजबूत बनाने और विषम परिस्थितियों में केदारनाथ पुर्ननिर्माण कार्य को अंजाम देने को लेकर मैं उन से प्रभावित हुआ हूँ। जबकि आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में जो कार्य किए हैं वे जग जाहिर हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में कार्यकताओं की न केवल उपेक्षा हो रही थी बल्कि यूथ को केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस कारण पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा। जनता का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ कार्य किया जायेगा।

समस्त देश–प्रदेश एवं रूद्रप्रयाग जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

नरेन्द्र बिष्ट
जिला पंचायत सदस्य
रूद्रप्रयाग

स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

—बलदेव नेगी
सामाजिक कार्यकर्ता

स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

—शत्रुघ्न नेगी
अध्यक्ष कार्तिक मंदिर समिति एवं प्रदेश संगठन मंत्री प्रातीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखण्ड

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

आईए! राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाए!

सुरेन्द्र रावत
वार्ड नम्बर 4
नगर पालिका रूद्रप्रयाग

स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

—नवल कुमार
अधिशासी अभियंता
जल निगम,
रूद्रप्रयाग

समस्त देश प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां।

आइए राष्ट्र इस स्वतंत्रता दिवस संकल्प लें कि राष्ट्र के चहुंमुखी विकास के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें

शशि नौटियाल
ग्राम-प्रधान सेमा
जखोली रुद्रप्रयाग

प्योर हिल नेचर खंड़पतिया

एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुद्धता की ग्रारंटी हमारी।

हमारे यहां पहाड़ी उत्पाद– जूस, स्क्वैश, अचार, जैम, चटनी, सॉस, सिरका, आर0टी0एस0, मंडुवा, झंगोर एवं विभिन्न पहाड़ी दालें उचित मूल्य में मिलते हैं।

–प्रो0 उर्मिला नेगी

रूद्रप्रयाग–पोखरी मार्ग खड़पतियां (रूद्रप्रयाग) मो0 8630079439

बताओं उत्तराखण्ड सरकार! सीता की 'विदाकोटी' को ये कैसा अज्ञातवास?

मुहुर्मुहुरू परावृत्य दृष्ट्वा सीतामनाथवत्।
चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मणारू प्रययावथ।

गंगा जी के तट पर अनाथ की तरह रोते हुऐ धरती पर लोट रही विदेहनन्दिनी सीता के लिऐ वाल्मीकी रामायण उत्तरकाण्ड ४८ सर्ग में वर्णित इस श्लोक का सार आज भी नही बदला है। विलख रही सीता को विदा करते हुऐ तब लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर देखते हुऐ चल दिऐ वैसे ही आज हम सभी देवप्रयाग में गंगा अलकनन्दा के तट पर रामायणकाल के इस अलौकिक तीर्थ ६ विदाकोटी ६ को देखकर भी मुंह मोड़ देते है। विडम्बना देखे की ६ सीता सर्किट ६ की जोर शोर घोषणा होने के बाद भी सरकार और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारियां यहां शून्य है। जबकि उत्तराखण्ड सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजना ६ सीता सर्किट ६ के अन्तर्गत विदाकोटी, सीतासैंण, कोट सीता मंदिर को विकसित करने जा रही है। लेकिन इस योजना के परवान चढ़ते–चढ़ते गंगा तट पर मां सीता के पहले आश्रयस्थल विदाकोटी का अस्तित्व संकट में आ चुका होगा। दरसल विदाकोटी के नारायण मंदिर की दीवारे और शिखर अधिकांशतरू क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिसके कभी भी ढहने की आशंका बनी हुई है। कभी गुलजार रहने वाला इसका रास्ता झाड़ियो से ढककर जंगली जानवरो की शरणस्थली बन चुका है। आखिर राम को आदर्श मानने वाली सरकार में राम की सीता को लेकर भाव क्या कुंद हो चुका है?

वियावान बसेरे में 80 साल के बुजुर्ग का अज्ञातवास

विदाकोटी के नारायण मंदिर में 80 साल से पूजा कर रहे बुजुर्ग पुजारी सुदंरलाल भट्ट अपने पुत्र के साथ इस वियावान में अकेले रह रहे है। यहां आने का रास्ता आज भी वही पुराना बद्रीनाथ मार्ग है जिस पर आजादी से पूर्व पैदल यात्रा चला करती थी। हालांकि अब यहां सड़क कट रही है जिस पर भी फिलहाल काम बंद है। जंगल का रास्ता होने से यहां आवाजाही ना के बराबर है। भगवान की नियमित पूजा और उनकी गुजरबसर कैसे होती होगी यह भगवान भरोसे ही है। यहा बसे सभी परिवार पलायन कर चुके है। बावजूद अपने आराध्य की पूजा के लिऐ वो 80 बरस अर्पित कर चुके है। वो चाहते है उनके बाद भी यह ऐतिहासिक स्थली बची रहे। सीता माता की यह धरोहर टूटने को है समय रहते इसे बचा दिया जाय। सड़क और रास्ता बने तो आवाजाही सरल हो जायेगी। राम की सीता के लिऐ उत्तराखण्ड सरकार कुछ तो राजधर्म निभाऐ।

विदाकोटी जहां विदा हुई सीता

देवप्रयाग के निकट अलकनंदा के दूसरे छोर पर दिखाई देने वाला विदाकोटी का यह प्राचीन मंदिर नारायण का है। इसका नाम विदाकोटी सीता की विदाई से उपजा है। रामायण के उत्तरकाण्ड के सर्ग ४७ – ४८ में इससे जुड़े प्रसंग का जिक्र है। त्रेतायुग में इसी स्थान पर लक्ष्मण जी मां सीता को विदा करने पहुंचे थे। कुछ समय तक भगवान नारायण की पूजा करने के उपरांत मां सीता यहा से दो किलोमीटर आगे एक समतल सैंण में कुटिया बनाकर रहने लगी। बाद में वे यहां से कोट गांव चली गयी। तब से सीतापथ का यह रास्ता ऐतिहासिक हो गया। किन्तु बद्रीनाथ के सड़क मार्ग बन जाने के बाद यहा आवाजाही लगभग बंद हो गयी। विदाकोटी से दो किलोमीटर आगे सीतासैंण से सीता की मूर्ति को मुछियाली गांव ले जा दिया गया। सीता का यह पथ विदाकोटी से सीतासैंण, मुछियाली, कोट, फलस्वाड़ी तक फैला है।

दीपक बेंजवाल

पुरातत्व और पर्यटन विभाग ले सुध

विदाकोटी नारायण मंदिर धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, पुरातत्व की दृष्टि से उतना ही ऐतिहासिक भी। इसस मंदिर का शिखर, गर्भगृह की दीवारे क्षतिग्रस्त हो चुकी है। समय रहते इसे बचाया न गया तो यह विरासत नष्ट हो जायेगी।

कब साकार होगी सीता सर्किट योजना

उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सीता सर्किट के लिऐ घोसणा कर चुके है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी केन्द्र सरकार को भी इसे विकसित करने का प्रस्ताव भेजा जा गया है। लेकिन अभी तक यह योजना धरातल पर नही उतर पायी है।

उत्तराखंड में ठोस भूमि कानून की जरूरत

चारू तिवारी

कोरोना के चलते पहाड़ वापस आ रहे कामगारों को यहीं रोजगार देने के लिये सरकार ने प्रयास करने की बात कही है। पहाड़ से पेट के लिये लगातार हो रहे पलायन को रोकने की नीति तो राज्य बनने से पहले या अब राज्यत् बनने के शुरुआती दौर से ही बन जानी चाहिये थी। जब सरकार ने ऐसी मंशा व्यक्त की तो आज तक के अनुभवों को देखते हुये मैंने एक सिरीज शुरू की थी– 'पलायन 'व्यक्तिजनित' नहीं 'नीतिजनित' है। इसकी पहली कड़ी में राज्य में मौजूदा कृषि भूमि की स्थिति को रखा। आज दूसरी कड़ी लिखने बैठा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत जी का टीवी चौनल में साक्षात्कार देखा। उसमें उन्होंने वही घिसी–पिटी बातें कहीं, जिनके चलते लोगों को सरकार की नीतियों से विश्वास उठता रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने साक्षात्कार में 2018 में अपनी उसी विवादास्पद 'इंवेस्टर्स समिट' का हवाला दिया, जो बड़े पूंजीपतियों के लिये वरदान और हमारे लोगों को पहाड़ छुड़वाने वाली साबित हुई है। माना जा रहा था कि कोरोना के बहाने ही सही शायद नीति–नियंता अब कुछ बेहतर सोच रहे होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री आज भी उसी 'इंवेस्टर्स समिट' का हवाला दे रहे हैं। उसे ही उत्तराखंड की प्रगति का आधार मान रहे हैं। हालांकि यह साक्षात्कार इतना सतही था कि इस पर ज्यादा बातचीत नहीं की जा सकती। हां, मुख्यमंत्री ने जो रटा–रटाया बोला, अगर वही नीति पलायन को रोकने की है तो यह बहुत अफसोसजनक है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने 'जी बिजनेस' टीवी चौनल को दिये गये साक्षात्कार में कहा कि हम ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिससे 'गांव का पलायन गांव' में ही हो। यह एक किस्म से नया जुमला है। नई शब्दावली भी। इसके सपोर्ट में उन्होंने जो बात कही वह और चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गांव में रोजगार पैदा करने के लिये नई टाउनशिप डेपलप करना चाहते हैं। इन टाउनशिप में अच्छे स्कूल और अस्पताल खुल सकें, रेस्टोरेंट, होटल खुल सकें, बड़े बाजार बन सकें ताकि हम लोगों को यहीं रोजगार दे सकें। इसके लिये 88 ग्रोथ सेंटर खोल गये हैं, जो पहले शहरों में थे। तेरह जिलों में डिस्टनेशन सेंटर खोलने की नीति बनाई है।

उन्होंने 2018 में हुये 'इंवेस्टर्स समिट' का हवाला देते हुये बताया कि उनके प्रयासों से राज्य में निवेशकों ने 1 लाख 24 हजार करोड़ के निवेश की इच्छा जताई थी। जिनमे से 23 हजार करोड़ के निवेश से यहां निवेशक अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य बनने के बाद यहां निवेशकों ने 39 हजार करोड़ का निवेश किया था। इसी के आलोक में उन्होंने पूरे विकास का खाका खींचा है। मुख्यमंत्री ने इस साक्षात्कार में उसी तरह की बातें की हैं जो राज्य बनने के बाद दोहराई जाती रही हैं। जैसे हार्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुगंधित पादप खेती, गुलाब की खेती, को–आपरेटिव से ऋणमुक्त ब्याज, परंपरागत उपज को बढ़ावा आदि–आदि। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार के पास कोई ऐसा रोडमैप नहीं है जो आने वाले दिनों में पलायन रोकने के लिये किसी ठोस नीति पर काम कर सके। इन सब बातों को लोग दशकों से सुनते आये हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत जी 6 अक्टूबर 20018 को जब देहरादून में देशभर के उद्योगपतियों को 'इंवेस्टर्स समिट' के नाम पर बुलाया था तो ऐलान किया था कि वह राज्य में ऐसा भूमि कानून संशोधन लायेगी, जिससे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी घोषणा के अनुपालन में सरकार ने 6 दिसंबर, 2018 को 'उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकलन एवं उपरांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश–2018' को विधानसभा में रखा था। इसे 8 दिसंबर को पास कर राज्यपाल की मंजूरी के लिये भेजा गया था।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश ने नये भूमि कानून का रूप लेकर पहाड़ों में जमीनों की बेतहाशा लूट का रास्ता खोल दिया। इस संशोधन के अनुसार अब पहाड़ में किसी भी कृषि भूमि को कोई भी कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है। पहले इस अधिनियम की धारा–154 के अनुसार कोई भी कृषक 12.5 एकड़ यानि 260 नाली जमीन अपने पास रख सकता था। इससे अधिक जमीन पर सीलिंग थी। नये संशोधन में इस अधिनियम की धारा 154 (4) (3) (क) में बदलाव कर दिया गया है। नये संशोधन में धारा 154 में उपधारा (2) जोड़ दी गई है। अब इसके लिये कृषक होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 12.5 एकड़ की

बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग के प्रयोजन के लिये कितनी भी जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं नये संशोधन में अधिनियम की धारा– 143 के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया। पहले इस अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि को अन्य उपयोग में बदलने के लिये राजस्व विभाग से अनुमति जरूरी थी। अब इस संशोधन के माध्यम से इस धारा को 143 (क) में परिवर्तित कर दिया गया है। अब अपने उद्योग के लिये प्रस्ताव सरकार से पास कराना है। इसके लिये खरीदी गई कृषि जमीन का भू–उपयोग बदलने की भी जरूरत नहीं है। इसे बहुत आसानी से अकृषक जमीन मान लिया जायेगा। इस इस संशोधन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहाड़ में उद्योग लगाने के लिये किसी भी निवेशक को जमीन खरीदने की छूट प्रदान करती है। इससे आगे बढ़कर सरकार ने इसी कानून की धारा–156 में संशोधन कर तीस साल के लिये लीज पर जमीन देने का अध्यादेश पास किया है। इससे समझा जा सकता है कि कृषि से रोजगार देने की बात करने वाली सरकार के दावे कितने खोखले हैं।

देश के अन्य हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को समझते हुये यहां बहुत सख्त भू–कानून बनाये गये हैं। जम्मू–कश्मीर में संविधान की धारा–370 और 35–ए (अब हटा दी गई हैं) से जमीनों की खरीद–फरोख्त पर रोक थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में धारा–371–ए के माध्यम से जमीनों को बचाया गया है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीनों को बचाने के लिये धारा–118 बनाई है। इन राज्यों ने पहले अपनी जमीन को बचाया और फिर इसको विकसित करने का काम किया। यही वजह है कि जहां हिमाचल प्रदेश को आज हम 'एप्पल स्टेट' के रूप में जानते हैं तो सिक्किम को 'जैविक राज्य' के रूप में। हिमाचल प्रदेश में 'हिमाचल प्रदेश टेंनसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट–1972' के 11 वें अध्याय में 'कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड' में धारा–118 है। इस धारा के अनुसार हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी कृषि जमीन को हिमाचल का रहने वाला ही गैर कृषक भी नहीं खरीद सकता। इसी धारा का 38–ए का सैक्शन–3 यह भी कहती है कि कोई भी भारतीय (गैर हिमाचली) रिहायशी जमीन खरीदने के लिये आवेदन कर सकता है। इसकी सीमा भी 500 स्क्वायर मीटर होगी। लेकिन इसके लिये भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। गैर हिमाचली सरकारी कर्मचारी भी अगर अपना आवास बनाना चाहें तो उनके साथ भी हिमाचल में तीस साल की सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिये। इस प्रकार के प्रावधानों ने वहां की कृषि योग्य जमीन को बचाने का काम किया है।

सिक्किम में भी ठोस भू–कानून है। यहां भी कोई गैर सिक्किमवासी जमीन नहीं खरीद सकता। सिक्किम की 'दि सिक्किम रेग्युलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड (एमेंडमेंट) एक्ट 2018 की धारा–3 (क) में यह प्रावधान किया गया है कि लिम्बू या तमांग समुदाय में ही जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। इसमें भी यह प्रावधान किया गया है जमीन बेचने वाले को कम से कम तीन एकड़ जमीन अपने पास रखनी होगी। यह प्रावधान इसलिये किया गया कि जो जमीन बेच रहा है वह भूमिहीन न रहे। इसमें यह भी प्रावधान है कि केन्द्र द्वारा अधिसूचित ओबीसी को अपने पास तीन और राज्य द्वारा अधिसूचित ओबीसी को दस एकड़ जमीन अपने पास रखनी होगी। मेधालय में में जमीनों की खरीद–फरोख्त पर पाबंदी है। 'दि मेघालय ट्रांसफर ऑफ लैंड (रेग्युलेशन) एक्ट 1971 में प्रावधान है कि कोई भी जमीन आदिवासी को नहीं बेची जा सकती। दुर्भाग्य से जिस जमीन को बचाकर नीति नियंताओं ने गांवों को बसाने की नीतियां बनानी चाहिये थी वे बेशर्मी के साथ सबसे पहले जमीनों को बेचने में लग गई। उत्तराखंड में हमेशा जमीनों के सवाल को लेकर जनता आंदोलित रही है। राज्य आंदोलन के समय भी यह मांग रही है कि राज्य में ऐसा भू–काननू आना चाहिये जिससे हमारी जमीनों को बेचने से रोका जाये। लेकिन सरकारें लगातार जनता को गुमराह कर इन जमीनों के सौदे करती रही हैं। आज जब मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत और उनके नीति–नियंता यह बात कर रहे हैं कि वे पलायन को रोकना चाहते हैं तो वे जमीनों के सवाल पर चुप क्यों हैं? क्या हम यह उम्मीद लगा सकते हैं कि कोरोना त्रासदी को जिस तरह मुख्यमंत्री 'अवसर' के रूप में देख रहे हैं, यह अवसर भूमि कानूनों को बदलने के लिये भी होगा या हमेशा की तरह हवाई विकास की बात होती रहेगी।

अगर सरकार समझती है कि पहाड़ से पलायन को रुकना चाहिये तो सबसे पहले उन्हें गांवों को बसाने की बात करनी चाहिये। गांव बसाने के लिये जमीन चाहिये। जमीन के लिये जनपक्षीय भू–कानून और भू–प्रबंधन चाहिये। क्या सरकार ऐसा सोच रही है? अगर सोच रही होती तो हमारी जमीनों को लीज पर देकर 'कांटेक्ट फार्मिंग ' के बहाने बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश नहीं करती। जब लोग कोरोना संकट से जूझ रहे थे सरकार ने चुपके से 'कांटेक्ट फार्मिंग' का मसौदा पास करा दिया। सरकार ने प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर लोगों की जमीनों को लीज पर देने के लिये बड़े निवेश का प्रस्ताव पहले से ही किया हुआ है। और भी बहुत सारी योजनायें सरकार की प्रस्तावित हैं, जो बड़े पैसे वालों के लिये पहाड़ के गांवों की जमीनों को खरीदने का रास्ता तैयार करती हैं। सरकार उन लोगों को अपनी जमीन पर कुछ करने को प्रोत्साहित नहीं करती जो लगातार पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं।

(लेखक उत्तरखण्ड के लिए हमेशा चिंतनशील रहे हैं)

अर्थ कल लेंगे हमारे आज के संकेत

लड़ने-भिड़ने वाले रूद्रप्रयाग के युवा नेता मोहित डिमरी की कहानी

दीपक बेंजवाल

क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन, सूर्य की पहली किरन पहचानता है कौन, अर्थ कल लेंगे हमारे आज के संकेत। तुम न माने शब्द कोई है न नामुमकिन, कल उगेंगे चाँद–तारे, कल उगेगा दिन....कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों पर सटीक बैठती है जनाधिकारों के लड़ने–भिड़ने वाले एक युवा मोहित डिमरी की जिन्दादिली। जिला मुख्यालय से सटे स्वीली जवाड़ी गाँव के इस युवा ने पिछले कुछ सालों में वो कर दिखाया जो बहुत से नेता और जनप्रतिनिधि उम्र का बड़ा हिस्सा गुजारने पर भी नहीं कर पाए। मन्दाकिनी की गोद में बसे इस जनपद में जनाधिकारों के लिए जनता की आवाज बनने वाले जनाधिकार मंच के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने क्रान्ति की नयी शुरूवात की है। बतौर पत्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में आने पर जनसमस्याओं के बड़े जंजाल ने मोहित के मन में बड़ी गहरी उथल पुथल मचाई। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के कारण जनता की छोटी–बड़ी कई परेशानियाँ पहाड़ के पलायन रुपी आग में घी का काम कर रही थी। समय रहते इन्हें सुना और सुलझाया जाना आवश्यक था। फिर मोहित ने अपनी कलम को केवल खबर तक नही रखा बल्कि समाधान की दिशा में भी लगातार उठाना शुरू किया। धीरे–धीरे गाँव कस्बों के बहुत से लोगों को उनकी कलम ने न्याय दिलाना शुरू किया, तो बहुत से सोशल ऐक्टिविस्ट भी इनसे जुड़ने लगे। जिनमें क्रान्तिकारी युवाओं के साथ बु(िजीवी बुजुर्गो, पत्रकारों, सेवानिवृत शिक्षको, वकीलों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पेशेवर भी थे। छोटी समस्याओं के लिए लड़ने वाला यह जज्बा अब बड़े स्तर पर न्याय और संघर्ष के लिए तैयार हो उठा और नाम मिला जनाधिकार मंच। यह विशु(गैर राजनीतिक मंच था जिसमें सिर्फ जनसरोकारो के लिए आवाज उठाना ही प्रतिब(ता थी। मंच ने जिला प्रशासन के समक्ष संगठित रूप से गांव ग्रामीणों की समस्याओं को रखना शुरू किया, जिस पर त्वरित कार्यवाहियाँ होनी प्रारंभ हुई। मंच ने गैरसैंण राजधानी के समर्थन में जिला मुख्यालय समेत तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, जखोली में व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर अपनी व्यापकता का अहसास दिलाया। रुद्रप्रयाग जिले में आल वेदर रोड़ से प्रभावित हो रहे व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे बड़े अभियान से मंच को भारी जनसमर्थन मिला। मंच ने कोरोना लाकडाउन में फसे प्रवासियों की घरवापसी को लेकर चलाया गया सहायता अभियान भी सफल साबित हुआ और कई परिवार इससे सकुशल घर भी पहुंचे। मुहिम चलती है और चलती रहेगी के नारे के साथ जनसमस्याओं

के स्थायी समाधान के लिए वो लोकतंत्र की ताकत में अपना हिस्सा लेने के लिए कूद पड़े। जिला पंचायत सौरा जवाड़ी सीट से वे सदस्य के तौर पर चुनाव लड़े पर हार गए। चुनाव में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है लेकिन मोहित के लिए लोगों को जनना, समस्याओं को समझने के लिए इस चुनावी कम्पैन ने बड़ा अवसर दे दिया था। वो समझ गए कि यहां लोग गांवों में रहना चाहते है लेकिन सिस्टम उन्हें मूलभूत समस्याओं के लिए तरसाता है। यही असल मुद्दा है कि जनता के वाजिब मांगों की आवाज बनो। चुनावी हार के तुरन्त बाद ही वे भरदार क्षेत्र में पेयजल किल्लत दूर करने के अभियान में जुट गए। उन्होंने भरदार क्षेत्र के गांवों में संवाद स्थापित कर भरदार पेयजल संघर्ष समिति के आन्दोलन को धार दी परिणामतः आज इस योजना के तहत बुरांशखाल ;क्वीलाखालद्ध में लिफ्ट योजना की टेस्टिंग शुरू हो गयी। वो पिछले दो वर्षो से भरदार क्षेत्र में मोबाइल टावर के लिए भी प्रयासरत थे, जिसे हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। थाती दिगधार ;बड़माद्ध में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल, मनरेगा कर्मचारियों के ग्रेड पे और कोविड सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों और उपनल कर्मियों के मानदेय को लेकर भी उनके जनाधिकार मंच ने शोषितों और प्रभावितों की आवाज बुलंद कर सरकार को चेताने का प्रयास किया। जनसमस्याओं के इतर सामाजिक पहले भी उनके नेतृत्व में हुई। रुद्रप्रयाग जिले में रक्तदान को लेकर जागरूकता और स्वयंसेवीयों को तैयार करने की पहल हो या इन दिनों कोरोना महामारी के बीच गांव–गांवों आवश्यक दवाई किटों के वितरण का कार्य भी आमजन को राहत पहुंचाने में लगा है। मोहित डिमरी के जनसंघर्ष और सफलता की कहानियाँ बस इतने से नहीं रूकती बल्कि आए दिन वो किसी न किसी समस्या के लिए मुखर रहते है, और उसके समाधान की ओर ले जाने में जी जान से जुट जाते है। उनके ही शब्दों में कहे तो..

बेदिली! क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे।
सिर्फ ज़िंदा रहे हम तो मर जाएंगे।।

जिम्मेदारियों को जगाने का प्रयास

गाँव की बहुत सी जनसमस्याएं लंबे समय से फाइलों के धक्के खाती रहती है लेकिन कई बार अधिकारी इन पर गौर नहीं करते। मोहित डिमरी और उनके जनाधिकार मंच ने समस्याओं और रूकावटों की पड़ताल कर प्रतिनिधिमंडल बनाकर जिले के आला अधिकारियों के समक्ष धरातलीय साक्ष्यों को रखा साथ ही समाधान के लिए जनसंवाद स्थापित किया।

क्षेत्रीय हितों की अनदेखी पर राष्ट्रीय दलों को दिखाया आईना

राज्य मांग की मूल अवधारणा के प्रति हो रही उपेक्षाओं पर मोहित डिमरी बेबाकी से कहते है आखिर राज्य बनने के बाद मूल निवास, भू–कानून और गैरसैंण राजधानी की मांग को क्यों दरकिनार कर दिया गया। राज्य के एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी से जुड़कर उन्होंने राष्ट्रीय पार्टीयों की कार्यशैली को भी आइना दिखाया है। जिसमें क्षेत्रीय हितों को एक सिरे से दरकिनार कर दिया जाता है।

क्यों डरे हुए हैं उत्तराखण्ड के लोग?

अनसूया प्रसाद मलासी

उत्तर प्रदेश में रहते हुए सुदूर पर्वतीय अंचल के लोगों ने अपने यहाँ प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के समुचित उपयोग, यहाँ से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने और यहाँ के विकास के लिए पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया। आखिरकार क्षेत्रीय दल श्उत्तराखंड क्रांति दलश के झंडे के नीचे बृहद आंदोलन कर भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के इन नौ पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया गया।

9 नवंबर–2000 को भारतीय संसद ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। इन 20 सालों में उत्तराखंड में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्तराखंड जैसे पर्वतीय छोटे से राज्य में बाहरी राज्य और निकटवर्ती देशों के विस्थापित अल्पसंख्यक लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होना है। अपेक्षाकृत शाँत और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी चिंता और चिंतन का विषय बन गया है।

जनसंख्या के आँकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड के तराई जनपदों हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, देहरादून और नैनीताल में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में रोजगार और राजनीतिक वजूद बनाने के लिए शरण ले लिए हैं और वे यहाँ उत्तराखंड के स्थाई निवासी बन गए हैं। उत्तराखंड में सत्ता में बारी–बारी से रहे भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम वोट–बैंक के लिए राज्य की अवधारणा को ही दाँव पर लगा दिया है।

हाल ही में उत्तराखंड में भाजपा सरकार के (5 साल में) तीसरे मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के लोगों के माथे पर शिकन पड़नी स्वाभाविक है। पहला– राज्य की तमाम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का मामला 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा– तराई क्षेत्र, खासकर ऊधम सिंह नगर जनपद में बसे बंगाली समुदाय को जाति प्रमाण–पत्र और स्थाई निवास प्रमाण–पत्र देने में अब तक संयोजित 'पूर्वी पाकिस्तान' शब्द हटा दिया गया है।

इन दोनों मामलों में सीधा–सीधा कार्य मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। दरअसल, तराई क्षेत्र के मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में भाजपा पर्वतीय क्षेत्र में मुस्लिम घुसपैठ को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। रही सही कसर अब अरविंद केजरीवाल की श्आपश उत्तराखंड में अपने पाँव जमाने को लेकर कर रही है। 2022 के शुरुआती महीनों में देश के अन्य 5 राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है।

भाजपा को पता है कि धर्मभीरू उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हिंदू, हिंदुस्तान के नाम पर लोगों के वोट मिल जाएंगे और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के लिए वह मुस्लिम समुदाय पर डोरे डालने में कांग्रेस से कहीं आगे निकलने की होड़ में बनी हुई है।

उत्तराखंड में पलायन, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जंगली जानवरों से सुरक्षा, भू–कानून, स्थायी राजधानी आदि महत्वपूर्ण मुद्दे लोगों के सामने हैं। यह दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों पर मौन साध लिया है। वे यहाँ के मूल निवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में आनंदित हैं। आशंका है, इन्हीं सब वजहों से निकट भविष्य में पहाड़ के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर श्सरताजश बन जाएंगे।

इन पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ गाँव मुस्लिमों के बसे हुए हैं। उन्हें यहाँ सौ–डेढ़ सौ साल से अधिक समय हो गया है। अभी तक वे क्षेत्र के अन्य निवासियों की तरह यहाँ की परंपरा में रचे–बसे हुए हैं। गढ़वाली और कुमाऊँनी बोली बोलते हैं। मगर अब समय के साथ–साथ वह भी मार–मार कर मुसलमान बनाए जा रहे हैं। गाँव–गाँव में देवबंदी मौलवी आकर उनकी मस्जिदों में लाऊडस्पीकर लगाकर नमाज पढ़ रहे हैं। इससे भी क्षेत्र की शांति भंग हो रही है और लोगों में उनके प्रति दुराग्रह पनप रहा है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में राज्य के बाहर से आने वाले मुस्लिमों ने लघु उद्योग और व्यापार पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है। छोटे–छोटे कारोबार और स्वरोजगार में वह हर कदम आगे हैं। यहाँ का मूल निवासी अपने रोजगार के लिए जब संघर्षरत रहता है, तो बाहर के मुस्लिम समुदाय का कारोबार दिन दूनी– रात चौगुनी तरक्की करता है। लोगों में संशय है कि उनके पास इतना धन कहाँ से आ जाता है? कि कम समय में ही उन्होंने पहाड़ में आलीशान मकान और कारोबार बना दिया है। बीते दिनों हिंदुओं के पवित्र क्षेत्र और देश में चार धामों में एक श्री बदरीनाथ धाम में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने का मामला चर्चा में रहा है। इस पर्वतीय क्षेत्र के नगर, कस्बों में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई है कि निकट भविष्य में वे यहाँ जबरन अपने इबादतस्थल (मस्जिद) और कब्रिस्तान बना देंगे या फिर वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे। एक मुस्लिम मौलवी द्वारा श्री बदरीनाथ धाम को मुस्लिमों के बदरुद्दीन द्वारा बसाया गया कहकर एक अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई।

खालिस्तान आंदोलन के समय (आठवें दशक में) खालिस्तानियों द्वारा चमोली जिले के हेमकुंड लोकपाल मंदिर को भी अपनी सीमा में बता दिया गया था और पड़ोसी देश नेपाल से तो कोई वर्क परमिट सिस्टम लागू नहीं होने से प्रतिवर्ष वहाँ के हजारों लोग भी उत्तराखंड की इन कंदराओं में खपते जा रहे हैं। यह उत्तराखंड के लिए एक खतरनाक हालात पैदा करने के संकेत दे रहे हैं।

वेदना

सीमा रावत

तेरी ही डाल की एक पत्ती हूँ मैं,
है तेरा आगोश कहाँ?
क्यों मैं मुरझाती जा रही हूँ?
ले चल मुझे तेरी शीतलता जहाँ।

जल रही मैं तपती धरा पर,
है मुझ पर तेरी छांव कहाँ?
ये निर्मम हवा मुझे उड़ा रही,
समेट ले मुझे तेरा साया है जहाँ।

मैं आदी हूँ तेरी लोरियों की,
है आज तेरी संगीत कहाँ?
छुपा ले मुझे अपने आँचल में,
तेरा ममता का सुकून है जहाँ।

सपने तेरे तरूण लता से
करते नितदिन स्वांग नया
पूछे मुझे कहाँ है उड़ना?
मैं कटी मूल सी बेसुद्ध यहाँ।

आते जाते पंथी पूछे?
है तेरा आश्रय कहाँ?
मैं बेजान सी पड़ी धरा पर
सोचूँ क्यों ना मुझे नजर बंद किया।

सन्नाटे काली घनी रातों के
करते अपना राग बयां।
कहते मुझसे क्यों हो जन्मी?
है तेरे जन्मदाता ईश कहाँ

इस कविता की रचनाकार वर्तमान में रूद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात हैं। यह कविता कवित्री द्वारा (घरेलू हिंसा व उत्पीड़न की शिकार एक विवाहित महिला की अपनी माँ के समक्ष प्रकट वेदना) का चित्रण किया है।

पहाड़ की 'माँ' का पहाड़ जैसा 'हौसला'

बेटी दसवीं में और खुद बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके बनी प्रेरणा स्रोत

संजय चौहान

कोरोना काल का सबसे ज्यादा खामियाजा स्कूल के छात्र छात्राओं को उठाना पडा। कोरोना काल इनके लिए दुःस्वप्न साबित हुआ। वहीं आज उत्तराखंड बोर्ड की दसवीं और 12 वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित किये गये।

पढ़ने–लिखने की कोई उम्र सीमा नही होती है। कुछ कर गुजरने की इच्छा और साहस के दम पर इंसान किसी भी उम्र में अपने कदम पढ़ाई के लिए बढ़ा सकता। आज आये उत्तराखण्ड की बोर्ड परीक्षा परिणामों में इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है ठेट पहाड़ की कमला रावत नें जिन्होनें अधूरी पढ़ाई को 17 साल बाद दुबारा शुरू करके पहले 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और आज 12 वीं की परीक्षा पास करके लोगों के लिए मिशाल बन गयी है। सीमांत जनपद चमोली के दशोली ब्लॉक के ठेल्ली गांव निवासी कमला रावत नें सही मायनों में बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के स्लोगन को हकीकत में बदल कर दिखा दिया है कि पहाड़ की बेटियों का जीवन केवल चूल्हा चौका, खेत खलिहान और कुदाल दरांती तक ही सीमित नहीं है अगर वो ठान ले तो आखर और कलम से अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। कमला रावत की एक बेटी 10 वीं में, एक बेटा 8 वीं में और दूसरा बेटा 5 वीं में है और वह खुद नंद्रप्रयाग से इस साल 12 वीं की परीक्षा पास करके पहाड़ की बेटियों के लिए नये प्रतिमान स्थापित कर गयी है।

बेहद अभावों और संघर्षो से भरा रहा जीवन. कमला रावत का जीवन बेहद संघर्षमय रहा। बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखनें वाली कमला नें बेहद गरीबी और घर से स्कूल दूर होने के कारण मजबूरी में कक्षा 8 की पढाई के बाद आगे की पढाई छोड थी जबकि कमला के अन्य सभी सहपाठियों ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। कमला आगे तो पढ़ना चाहती थी पर गरीबी और परिस्थितियों के आगे कमला चाहकर भी आगे की पढाई नहीं कर पाई, इस बात का कमला को आज भी बहुत अफसोस होता है। समय बीतता गया और कमला की शादी भी हो गई। ससुराल में गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाली और वो अपने बच्चों के लालन पालन में व्यस्त हो गयी। जब कमला अपने बच्चों को स्कूल जाते और पढ़ाई करते हुये देखती थी तो उसको अपनी अधूरी पढ़ाई की टीस हमेशा कचोटती रहती थी।

शिक्षिका और परिवार से मिला प्रोत्साहन!

कमला रावत कहती है कि मायके में अभावों में जीवन बीता तो ससुराल में परिवार कीसारी जिम्मेदारी निभानी होती है। इसलिए कभी अपने लिए सोचने का समय ही नहीं मिला।कुछ वर्ष पहले ही हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय मैड ठेली में एक शिक्षक की कमी थी ग्राम प्रधान एवं सभी ग्रामीणों की आपसी सहमति से कुछ महीने मैंने वहां पर बच्चों को पढ़ाया उसी दौरान विद्यालय की प्रधानाअध्यापिका जी से बात हुई क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था कि मैं आठवीं पास थी तब उन्होंने मुझे आगे पढ़ने का सुझाव दिया जो मेरे लिये असंभव भी था मन में पढ़ने की इच्छा भी थी। इसी बीच मेरे बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे, मेरे बच्चे उस समय खुद छठवीं आठवीं कक्षा में पढ़ रहे थे। इसलिए मैने आगे पढने की बात अपने परिवार के संग साझा की तो वो सभी बेहद खुश हुए और सबने मुझे अधूरी पढ़ाई को पूरी करनें और आगे पढाई जारी रखनें को प्रोत्साहित भी किया। कहती है कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है, जिसे लोग कहते हैं, कि ये तुम्हारे बस का नहीं है.. बस इसी बात को मन में गांठ की तरह बाँध ली थी फिर 17 साल की अधूरी पढ़ाई पूरी करते हुये पहले हाईस्कूल की परीक्षा पास की और आज 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनें के बाद मैं बहुत खुश हूँ आखिरकार वर्षों पहले देखा मेरा सपना साकार हुआ है। मैं चाहती हूं कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे खासतौर पर बेटियां चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। यदि भविष्य में संभव हो पाया और मां भगवती की कृपा रही तो जीवन का यह संघर्ष जात्रा लघु फिल्म के माध्यम से भी लोगों के सामने लाने की कोशिश रहेगी।

भले ही 5 साल पहले तक कमला खुद को अनपढ समझती हो लेकिन उसने अपने कार्यों से लोगों को ये आभास ही नहीं होने दिया था की वो इतनी कम पढी लिखी है। वो हमेशा से ही सामाजिक कार्यों.. स्वच्छता, गांव की समस्याओं, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, के स्लोगनों को धरातल पर क्रियान्वित करने में बढ चढकर हिस्सा लेती है। गांव की सांस्कृतिक विरासत हो या अन्य सबको बखूबी निर्वहन करती। माँ नंदा के लोकगीतों और जागरों को संजोना हो या फिर हरेला के पारम्परिक त्यौहारों को मनाना ये भला कोई कमला रावत से सीखें। डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे अपनी बात रखनी है ये भी कमला रावत से सीखा जा सकता है। **दूँढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे... .मंज़िलो की फ़ितरत है खुद चलकर नहीं आती है उक्त पंक्तियों को सार्थक कर दिखाया है कमला रावत नें. पहाड़ की इस मां को हजारों हजार**

हुनर हो तो ऐसा! बेजान लकड़ी में उकेरा पहाड़ का लोकजीवन

संजय चौहान

संजय चौहान! हुनर है तो बेजुबान पत्थर भी बोल उठते हैं। बेकार पडी लकड़ी में जान आ जाती है। ऐसे ही हुनरमंद हस्तशिल्पि हैं टिहरी जिले के दिनेश लाल। ये विगत 7 सालों से लकडी पर विभिन्न प्रकार के मंदिरों के डिजाइन, पहाड़ के लोक वाद्य यंत्र, पहाडी घर सहित अन्य कलाकृति बना रहें हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने दो महीने में बेजान लकड़ी पर एक पहाडी गांव बना दिया। जिसमें पहाड़ के गांव की हर दिनचर्या उकेरी है। या यों कहिए की पहाड़ के लोकजीवन का सजीव चित्रण किया है। जो भी इस कलाकृति को देख रहा है वो अचंभित हो रहा है। बकौल दिनेश पहाड़ी गांव को बनाने में दो महीने लग गये। इसमें 95: लकडी का प्रयोग किया गया है जबकि हुबहु गांव दिखने के लिए कुछ असली पत्थर, मिट्टी को जमीन उंची नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया है। सारी मूर्तियाँ लकड़ी पर बनी है वह भी सिर्फ एक सेंटीमीटर से कम की लंबाई में। मैं अपने काम से संतुष्ट और बेहद खुश है।

सूखी और बेजान लकड़ी में फूंकते है जान!

दिनेश की हस्तशिल्प कला इतनी बेहतरीन है कि वो सूखी और बेजान लकड़ी में भी इतनी शानदार नक्काशी करते है कि कलाकृति बोल उठती है और जींवत हो उठती है।

पहाड़ी घर, केदारनाथ मंदिर, और ढोल दमाऊं की कलाकृति के हुये लोग मुरीद। यों तो दिनेश नें अपनी हस्तशिल्प कला के जरिए दो दर्जन से ज्यादा कलाकृतियों को आकार दिया है। हुक्का, बैल, हल, परेडा/परय्या, लालटेन, चिमनी, कृष्ण भगवान का रथ, तलवार, धनुष, गधा, तीर, ओखली, गंज्यालु, टिहरी का घंटा घर, केदारनाथ मंदिर के डिजायन, अयोध्या मंदिर का डिजाइन सहित दर्जनों कलाकृति सम्मिलित है। जिसमें से पहाड़ी घर, केदारनाथ मंदिर, और ढोल दमाऊं की कलाकृति लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई है। लोग इन मॉडलो के मुरीद हुये। कई लोगों नें इन मॉडलो को खरीदा भी।

वास्तव मे देखा जाय तो आज हमारी वैभवशाली अतीत का हिस्सा रही बेजोड़ हस्तशिल्प कला आज दम तोडती नजर आ रही है। बस यदा कदा ही लोग बचें है जो इस कला को बचाये हुये हैं। ऐसे मे हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे हुनरमंदो को प्रोत्साहित करने को और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की। अगर आपको दिनेश लाल जी की बनाई कलाकृतियाँ पसंद है तो उनसे इस दूरभाष नंबर पर संपर्क कर अपनी डिमांड दे सकते हैं।

'पुनर्वास' की आस में 531 'परिवार'

सोनिया मिश्रा

आपदा प्रभावित रुद्रप्रयाग के 531 परिवार वर्षों से पुनर्वास की राह देख रहे हैं। केदारनाथ आपदा के बाद से बीते वर्ष तक जिले के 27 गांवध्तोक के 591 परिवारों को पुनर्वास की सूची में शामिल किया जा चुका है लेकिन आठ वर्ष में सिर्फ 60 परिवारों का ही उनकी अन्यत्र भूमि में पुनर्वास हो पाया है।

वर्ष 1997 में अलग जिला गठन के बाद से वर्ष 1998 से 2020 तक जिले में कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं, जिससे यहां के कई गांव बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। ये गांव वर्षों से पुनर्वास की मांग करते आ रहे थे। वहीं, 16ध्17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा में तबाही के बाद जिला स्तर पर प्रशासन ने राजस्व विभाग व भू–वैज्ञानिकों की मदद से कई चरणों में प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण करवाया। वर्ष 2014 में भूगर्भीय सर्वेक्षण एवं 2011 की पुनर्वास नीति के आधार पर जिले के कुल 23 गांवों के 472 परिवारों को पुनर्वास सूची में शामिल किया गया। अब तक सात गांवों के सिर्फ 60 परिवारों को ही उनकी अन्यत्र भूमि में पुनर्वास किया जा सका है जबकि बीते वर्ष 119 और प्रभावित परिवार सूची में शामिल किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा, पूर्व ग्राम प्रधान कुंवरी बवाल, भारत भूषण नेगी, भगवती प्रसाद जोशी, प्रेम प्रकाश जोशी, आरएस रौथाण, देवेंद्र बजवाल, कुलदीप राणा, पुष्पा देवी का कहना है कि शासन–प्रशासन को सैकड़ों पत्र भेजे जा चुके हैं। अब तक प्रभावित गांवों का पुनर्वास नहीं हो पाया है।

पुनर्वास सूची में शामिल गांव

पुनर्वास सूची में ग्राम पंचायत पांजणा, जैली, मूसाढूंग (सुनाई तोक), कालीमठ, कुणजेठी, जागतल्ला, बलसुंडी, बीरों–देवल का खाली तोक, सेमी तल्ली, दैड़ा, सिल्ला–ब्राह्मणगांव, चमराड़ा, गिरिया, कविल्ठा, ऊखीमठ, नागजई का जाख तोक, टेमरिया वल्ला, दिलमी, टाटलगा फेगू, डमार, मलाऊं, कुंडा–दानकोट का धोकाणी तोक, छांतीखाल, सिरवाड़ी गांव का देवी तोक, उषाड़ा गांव का ताला व कठाणी तोक और मक्कूमठ गांव का दिलणा तोक शामिल हैं। अब तक इनका हुआ पुनर्वास ऊखीमठ तहसील– सेमी तल्ला, कुणजेठी, कविल्ठा, जाल तल्ला– 42 परिवार। जखोली तहसील– पांजणा– 14 परिवार। रुद्रप्रयाग तहसील– 4 परिवार।

*पुनर्वास की प्रक्रिया शासन स्तर पर चरणबद्ध तरीके से चल रही है। मैं स्वयं भी सूची में शामिल गांवों का निरीक्षण कर वहां के हालातों की जानकारी लूंगा। हरसंभव प्रयास होगा कि अति संवेदनशील गांवों का प्राथमिकता से समयबद्ध पुनर्वास किया जाए। –**मनुज गोयल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग***

महँगा है मतदान हमारा

महँगा है मतदान हमारा,
हुआ निरंतर अपमान हमारा।
फिर लहू की बोली बोलेंगे।
इनको तब आएगा ध्यान हमारा।
अपने ही दुर्गति का कारण हैं,
जो छीन रहे हैं सम्मान हमारा।
जिस माटी पानी ने हमको सींचा,
माटी की खातिर क्या दान हमारा?
राजनीति की भेंट चढ़ गया है ,
युवा, विकास, और बलिदान हमारा।
एक बार फिर ध्वज फहराएंगे ,
फिर चाहे ये लूटें , प्राण हमारा।
जिन माँ बहनों ने तुमको श्रेष्ठ बनाया,
याद रहे अब वही लिखेंगे ,निर्वाण तुम्हारा।

पहाड़ अब अपना अस्तित्व , राजनेतिक
स्वार्थ के धनी लोगो के हाथ नहीं छोड़ेगा।
लड़ेगा और अपना हक पा कर रहेगा।

अरविन्द सेमवाल
प्रवक्ता
उत्तराखंड क्रान्ति दल

मेरी आँखों में बस जा

इतना ही स्वारथ है तुझ से,
मेरे आँखों में बस जा।
नहीं मतलब कुछ भी ज्यादा,
जरा राहों में सज जा।
इज्जत है दिल में तेरे लिए,
भले अस्वीकार कर लेना।
रखना चाहता हूँ पलकों पर,
बेशक नजरें चुरा लेना।
लायक भले न समझ मुझे,
बस जरा सा हंस जा।
इतना ही स्वारथ है तुझ से
बेदर्दी दिल तो नहीं है मेरा,
बेरहम मुझ पर हो जाना।
कल्पना ही तेरी कर लूंगा में,
झलक दूर से दिखा जाना।
दिखा दे मुझे तू पीठ सही,
पर जरा सा तो रुक जा।
इतना ही स्वारथ है तुझ से
ताजगी भरी है तेरे लिए,
तू रूखा पन अपना ले।
हृदय पिगलाता रहूंगा में,
तू दिल को पत्थर बना ले।
घूर घूर कर देख ले चाहे,
शान्त दिल को तू कर जा।
इतना ही स्वारथ है तुझ से
है जितनी सुन्दर सूरत तेरी,
चित भी उतना सुंदर होगा।
माया मोहनी सी लगती है,
जरूर श्रेष्ठ गुण भी होगा।
नहीं भी होगा प्रेम मेरे हित,
नफरत से ही प्यार भर जा।
इतना ही स्वारथ है तुझ से

–राजपाल पंवार

मत्स्य विभाग रूद्रप्रयाग की विभिन्न योजनाएं

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निमार्ण योजना (सभी वर्गों हेतु)

कच्चा तालाब निर्माण (50 वर्ग मीटर)	40 हजार के सापेक्ष (50 प्रतिशत)	20 हजार रूपये अनुदान देय।
प्रथम वर्षीय मत्स निवेश	10 हजार के सापेक्ष (50 प्रतिशत)	5 हजार रूपये अनुदान देय।
तालाब निर्माण एवं निवेश सहित	50 वर्ग मीटर (50 प्रतिशत)	25 हजार रूपये अनुदान देय।
निजि भूमि पर तालाब निर्माण (200 वर्ग मी.)	2 लाख 70 हजार के सापेक्ष (50 प्रतिशत)	1 लाख 35 हजार अनुदान देय)
प्रथम वर्षीय मत्स निवेश	30 हजार के सापेक्ष (50 प्रतिशत)	15 हजार अनुदान देय
तालाब निर्माण एवं निवेश सहित	3 लाख के सापेक्ष (50 प्रतिशत)	1 लाख 50 हजार अनुदान देय

2. विषेश संघठक उपयोजना– केवल अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों हेतु। एक लाभार्थि हेतु केवल 4 युनिट

कच्चा तालाब निर्माण एवं निवेश सहित (100 वर्ग मीटर)	1लाख 20 हजार पर 60 प्रतिशत	72 हजार रूपये देय।

3. मत्स्य पालक विविधीकरण योजना – (अ) समन्वित मत्स्य पालन (बत्तख बाड़ा)– अनुसूचित जाति हेतु राज्य अनुसूचित जाति के व्यक्तियो हेतु क्रियान्वित योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में बत्तख बाड़ा निर्माण एवं निवेश हेतु कुल लागत 1.39 लाख का 60 प्रतिशत रू0 0.83 लाख का अनुदान लाभार्थी को देय है। ब) **पर्वतीय तालाब सुधार** – यह अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की सामजिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु क्रियान्वित पूर्व में निर्मित मत्स्य तालाबों में सुधारीकरण कार्य एवं निवेश हेतु कुल लागत 0.70 लाख का 60 प्रतिशत का 0.42 लाख का अनुदान लाभार्थी को देय है।

4. राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना–मत्स्य पालकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाता है।

केन्द्र पोषित योजनायें–

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 1. शीत जल मात्सियिकी विकास योजना (नीलक्रांति) (अ) शीत जल मात्सियिकी विकास योजना(नीलक्रांति) (अ) परमानेंट फार्मिंग यूनिट/रेसवेज निर्माण एवं इनपुट–जनपद के ऊँचाई वाले स्थलो पर ट्राउट फार्मिंग योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत 50 घनमी0 ट्राउट रेसवेज का निर्माण की एक यूनिट रेसवेज पर कुल लागत रू0 3,00,000.00 के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत धनराशि रू 1,20,000.00 एवं अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थी को 60 प्रतिशत धनराशि रू0 1,80,000.00 अनुदान देय होगा। शेष धनराशि लाभार्थी स्वयं वहन करेगा। ट्राउट रेसवेज हेतु प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 2,50,000.00 पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0. 1,00,000.00 एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 1,50,000.00 देय होगा। निवेश हेतु अनुदान की धनराशि लाभार्थी के खाते में न डालकर विभागीय खाते में जमा होगा जिसके बदले लाभार्थी को ट्राउट सीड एवं ट्राउट आहार उपलब्ध कराया जायेगा। एक लाभार्थी अधिकतम 04 यूनिट हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है।

2.इन्फास्ट्रक्चर एवं मार्केटिंग (नीलक्रांति)–(अ) मोटर साईकिल विद आइसबॉक्स– योजनान्तर्गत मत्स्य पालकों को मोटर साइकिल विद आईस बॉक्स उपलब्ध कराये जाएंगे, इस मद के अन्तर्गत एक मोटर साईकिल विद आईस बॉक्स का क्रय मत्स्य पालक द्वारा किया जाएगा। जिस क्रय की कुल लागत रू0 75,000.00 के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत धनराशि रू0 30,000.00 एवं अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थी को 60 प्रतिशत धनराशि रू0 45,000.00 अनुदान देय होगा। शेष धनराशि लाभार्थी स्वयं वहन करेगा।

(ब)फिश कियोस्क (Fish Kiosks) का निर्माण– राज्य में समस्त जाति वर्ग के कार्यरत मत्स्य पालक के मत्स्य पालन व्यवसाय की निरन्तरता बनाये रखते हुए कार्यरत व नवीन मत्स्य पालकों को मात्स्यिकी अन्तर्गत विविध प्रणालियों यथा Aquarium/Ornamental Fisheries को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विशिष्ट संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रति कियोस्क की स्थापना हेतु कुल लागत रू0 10,00,000.00 के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 40 प्रतिशत धनराशि रू0 4,00,000.00 एवं अनुसूचित जाति एवं महिला लाभार्थी को 60 प्रतिषत धनराषि रू0 6,00,000.00 अनुदान देय होगा। शेष धनराशि लाभार्थी स्वयं वहन करेगा।

मत्स्य विभाग की अन्य योजनाओं के लिए कार्यालय विकास भवन, रूद्रप्रयाग में आकर भी प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद मत्स्य प्रभारी
रूद्रप्रयाग

लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग

समस्त देश प्रदेश वासियों को लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई वं शुभकामनाए!

सड़कें राष्ट्र की सम्पत्ति हैं इनके रख-रखाव में अपना सहयोग दें।

-इन्द्रजीत बोस
अधिशासी अभियंता
लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

स्वच्छ रूद्रप्रयाग

नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग

सुन्दर रूद्रप्रयाग

नगर वासियों से अपील

1. अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के गीले (जैविक) एवं सूखे (अजैविक) कूड़े को अलग-अलग कूडेदानों में रखकर अपने क्षेत्र में आने वाले पर्यावरण मित्रों को दें अथवा दो बिन वाले कूड़ा वाहन में ही डालें।
2. भवनकर, व्यवसाय लाइसेंस शुल्क व निर्धारित यूजर चार्च का समय पर भुगतान करें।
3. अपने घरों, प्रतिष्ठानों के आस-पासकूड़ा न फैलायें व सार्वजनिक स्थलों पर थूकें जाने पर 'उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकने एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक-2016' के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है इसका उल्लंघन करने पर रू0 5000/- तक जुर्माना एवं 2 साल की कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।
4. नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक व थर्माकोल से बने दोने पत्तल गिलास, कप, प्लेट चम्मच आदि को बेचा जाना रखा जाना एवं स्टोर किये जाने के साथ प्रयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त सामग्री प्राप्त होती है अथवा प्रयोग की जाती या चलन में लाई जाती है तो उस पर 5000.00 तक का अर्थदण्ड एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही हो सकती हे।
5. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपने मुँह व नाक को मास्क या कपड़े से ढक कर ही यदि अति आवश्यक तो ही घर से बाहर निकलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के आप पर जुर्माना हो सकता है।
6. सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचायें, ये आपके लिए हैं। अपने नगर को साफ एवं सुन्दर बनाये रखें व भारत सरकार के द्वारा किये जाने वाले आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अगस्त्यमुनि शहर को नम्बर 1 की रैंकिंग दिलवायें।

सीमा रावत
अधिशासी अधिकारी एवं समस्त
कर्मचारीगणनगर पंचायत, अगस्त्यमुनि

गीता झिंक्वाण
अध्यक्ष
एवं समस्त सभासदगण
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि

समस्त देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं जन्माष्टी में हार्दिक शुभकामनाएं!

सड़कें राष्ट्र की सम्पत्ति हैं यानि आप की हैं, इनके रखरखाव में सहयोग करें!

एस पी सिंह

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई पोखरी (चमोली)

आईए! राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाइए।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्वच्छ अगस्त्यमुनि सुन्दर अगस्त्यमुनि

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर वासियों से अपील

1. अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के गीले (जैविक) एवं सूखे (अजैविक) कूड़े को अलग–अलग कूडेदानों में रखकर अपने क्षेत्र में आने वाले पर्यावरण मित्रों को दें अथवा दो बिन वाले कूड़ा वाहन में ही डालें।
2. भवनकर, व्यवसाय लाइसेंस शुल्क व निर्धारित यूजर चार्च का समय पर भुगतान करें।
3. अपने घरों, प्रतिष्ठानों के आस–पासकूड़ा न फैलायें व सार्वजनिक स्थलों पर थूकें जाने पर 'उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकने एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक–2016' के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है इसका उल्लंघन करने पर रू0 5000/– तक जुर्माना एवं 2 साल की कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।
4. नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक व थर्माकोल से बने दोने पत्तल गिलास, कप, प्लेट चम्मच आदि को बेचा जाना रखा जाना एवं स्टोर किये जाने के साथ प्रयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त सामग्री प्राप्त होती है अथवा प्रयोग की जाती या चलन में लाई जाती है तो उस पर 5000.00 तक का अर्थदण्ड एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही हो सकती हे।
5. कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु अपने मुँह व नाक को मास्क या कपड़े से ढक कर ही यदि अति आवश्यक तो ही घर से बाहर निकलें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के आप पर जुर्माना हो सकता है।
6. सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचायें, ये आपके लिए हैं। अपने नगर को साफ एवं सुन्दर बनाये रखें व भारत सरकार के द्वारा किये जाने वाले आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अगस्त्यमुनि शहर को नम्बर 1 की रैंकिंग दिलवायें।

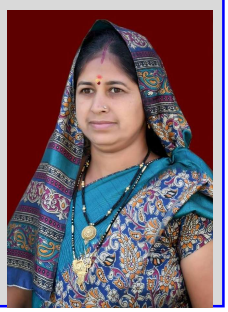

हरेन्द्र सिंह चौहान
अधिशासी अधिकारी
एवं समस्त कर्मचारीगण
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि

अरूणा बेंजवाल
अध्यक्ष
एवं समस्त सभासदगण
नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि

केदारखण्ड एक्सप्रेस की मुहिम लाई रंग

लता देवी को मिला आशियाना

एक बार फिर जन सरोकारों की पत्रकारिता पर खरा उतरते हुए आपकी लोक प्रिय पत्रिका एवं न्यूज पोर्टल केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज की मुहिम ने एक गरीब असहाय और हालातों की मारी लता देवी को सिर छुपाने के लिए आशियाना मुहैया करवा दिया हैं। रूद्रप्रयाग जनपद के जखोली विकास खण्ड के भरदार क्षेत्र के कोटली गाँव की लता देवी की दुःख भरी दास्तां केदारखण्ड एक्सप्रेस के न्यूज पोर्टल ने 6 मई 2021 को ''**दर्द भरी दास्तां : कोटली गांव की लता देवी ने नहीं देखी खुशियां, सिस्टम ने भी नहीं दिया साथ**'' नामक शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसके बाद समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों ने बढ़चढ कर लता देवी की मदद की और करीब ढाई लाख रूपये लता देवी के खाते में आए। जिसके बाद केदारखण्ड एक्सप्रेस के निर्देशन में उसके मकान बनाने का कार्य आरम्भ किया गया और अब दो कमरों के साथ लेटिन–बाथरूम और किचन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर गृह प्रवेश भी हो चुका है।

दरअसल मई माह के प्रथम सप्ताह में कोटली गाँव में हुए अतिवृष्टि से हुए नुकसान की कवरेज करने के लिए केदारखण्ड एक्सप्रेस की टीम करीब 4 किमी पैदल चलकर कोटली गाँव पहुँची थी। आपदा से हुए नुकसान की कवरेज करने के पश्चात यूकेडी नेता मोहित डिमरी हमारे संज्ञान में गाँव की लता देवी की दहनीय स्थिति को लाये। जब हमारी टीम लता के घर पर पहुँची तो वास्तव में हमें एक ऐसे सच से सामना हुआ जिस वेदना को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे। हमें मालूम है जीवन में हर किसी को कष्टों से गुजरना पड़ता है, सुख–दुख आते–जाते हैं, लेकिन जब दुःख जीवन भर के लिए कुडली मार कर बैठ जाय तो फिर क्या किया जा सकता है। लता देवी के हालात भी कुछ इसी तरह के नजर आ रहे थे।

घोर गरीबी के बीच लता देवी की शादी मंदबुद्धी व्यक्ति से हुई। लता ने सोचा था चलो बच्चें होंगे तो उनके सहारे जीवन की नैय्या पार होगी लेकिन पहली लड़की विकलांग पैदा हो गई और बाद में एक बेटा हुआ तो वह भी विकलांग पैदा हो गया। अब करीब लड़की 20 वर्ष की हो चुकी है और बेटा 17 वर्ष का। लेकिन ये दोनो बिस्तर के अलावा कहीं आ जा नहीं सकते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में दोनो बच्चों को दिखवाया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ऊपर से पति बेरोजगार और मंदबुद्धी होने के कारण तीन–तीन लोगों की लालन पालन की जिम्मेदारी अकेला लता देवी उठा रही है। लेकिन वह खुद भी अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। एक कमरे का घर कच्चा होने के कारण बरसात में तालाब बना रहता था जिससे लता देवी के जीवन में दुःखों का पहाड़ तो था ही, लेकिन हर रोज जीवन जीने की चुनौतियाँ उसे तिल–तिल मार रही थी।

लोगों की मदद से बना लता देवी का घर

केदारखण्ड एक्सप्रेस न्यूज ने लता देवी की इस दास्ताँ को प्रमुखता से प्रकाशित किया और समाज के बहुत सारे प्रबुद्धजनों ने लता देवी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और उसी की बदौलत आज लता देवी का आशियाना बनकर तैयार है। मदद करने वालों में विदेश में रहने वाले अगस्त्यमुनि के ईशान भट्ट और शिक्षिका लक्ष्मी शाह का विशेष योगदान रहा है, हालांकि मदद बहुत सारे लोगों ने की है जिनकी हमारे पास सूची भी नहीं है किन्तु लता देवी के प्रति व्यक्त की गई संवेदनाओं और मदद के लिए दी गई राशि के लिए केदारखण्ड एक्सप्रेस उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता है। आपने मानवता का अनुपम उदाहरण देकर इनसानियत को जिंदा रखने का फर्ज निभाया।

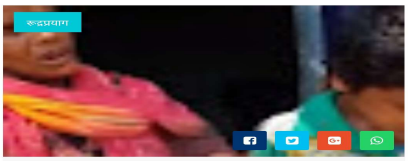

दर्द भरी दास्तॉं: कोटली गॉंव की लता देवी ने नहीं देखी खुशियां, सिस्टम ने भी नहीं दिया साथ

केदारखण्ड एक्सप्रेस May 06, 2021

दर्द भरी दास्तॉं: कोटली गॉंव की लता देवी ने नहीं देखी खुशियां, सिस्टम ने भी नहीं दिया साथ -कुलदीप राणा आजाद/केदारखण्ड एक्स...

Continue Reading

लक्ष्मी साह : संवेदनाओं से भरी समाज सेविका

डैस्क केदारखण्ड एक्प्रेस

जैसा नाम वैसा गुण भी। समाज सेवा से ओतप्रोत लक्ष्मी साह को पतंजलि के मंचों पर आपने अक्सर देखा होगा लेकिन इनके भीतर समाज के प्रति समर्पण की भावना भी किसी से छिपी नहीं है। गरीबों, पीड़ितों और असहाय लोगों की मदद को लेकर वे हमेशा आगे रहती हैं। केदारखण्ड एक्सप्रेस ने मई 2021 में रूद्रप्रयाग जनपद के कोटली गाँव की लता देवी की दुःख भरी खबर प्रकाशित की थी तो संवेदनाओं से भरी लक्ष्मी साह ने तुंरत फैसला कर दिया कि वे हर माह लता देवी को दो हजार रूपये देंगे और करीब छः माह से वे निरंतर लता देवी की मदद कर रही हैं। जबकि इससे पहले वे रूद्रप्रयाग जिले के बावई गांव में भी इसी तरह एक महिला की मदद लम्बे समय से कर रही हैं। लेकिन वे खूद को हमेशा प्रचार–प्रसार से बहुत दूर रखती हैं। लक्ष्मी दीदी ने हमसे भी इस बात को प्रकाशित करने से मना किया था किन्तु उनकी अनुमति के बिना यह खबर इस लिए प्रकाशित कर रहे हैं ताकि लक्ष्मी साह की यह प्रेरणा अन्य लोगों को मिलने साथ साथ समाज में नव चेतना का सृजन करें।

माँ–पिता से मिले संस्कारों ने जीवन में नई राह दिखाई और लक्ष्मी साह उन्हीं आर्दशों पर आगे बढ़ी। योग को अपनाकर पहले खुद से शुरू किया और अब विद्यालय से लेकर गाँव और प्रदेश में योग के जरिये लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की ललक और प्रतिबद्धता से परिपूर्ण शिक्षिका लक्ष्मी साह लोगों के लिए एक आदर्श बन गई हैं।

रूद्रप्रयाग जनपद के कोठगी (घोलतीर) निवासी शिक्षक श्री भगवान सिंह पंवार और श्रीमती सुशीला देवी के घर 30 मई 1974 को जन्मी लक्ष्मी पहाड़ी जीवन की कठोरता से बचपन से ही द्रवित होती थी। 1991–92 में श्रीनगर विश्वविद्यालय में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से सांस्कृतिक सचिव चुनीं गईं। इस जीत ने विश्वविद्यालय में बरसों से चले आ रहे इस मिथक को भी तोड़ा कि चुनावों में कोई लड़की कभी जीत नहीं सकती लेकिन लक्ष्मी के बुलंद हौसलों की यह जीत लड़कियों के लिए एक नजीर बनी।

शादी के बाद लक्ष्मी शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षिका सरकारी सेवा में आ गईं लेकिन साथ ही मन में छिपी समाजसेवा की भावना को आगे बढ़ाने का काम भी शुरू किया। स्कूल के बाद जो समय मिलता, उसे गाँव के लोगों की समस्याओं के निदान में लगातीं। वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करतीं। बच्चों के प्रति समर्पण और सेवाभाव को देखते हुए गाँव के लोग उन्हें शिक्षिका न कहते हुए 'गाँव की लक्ष्मी' कहकर पुकारने लगे। इसने लक्ष्मी को सेवा की नई प्ररेणा दी।

2001 में लक्ष्मी अचानक माईग्रेन के दर्द से ग्रसित हो गई, जिसके ईलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाये लेकिन कहीं भी सही ईलाज नहीं मिल पाया। यह सिलसिला 3–4 सालों तक चलता रहा। खुद लक्ष्मी को लगने लगा था कि अब षायद ही वह काम कर पायेंगी। लक्ष्मी की दिनचर्या स्कूल से घर तक ही सिमट गई थी। इसी बीच बाबा रामदेव के योग की पूरे देष में हो रही चर्चा से प्रभावित लक्ष्मी की माँ और पिता ने उन्हें योग करने की सलाह दी। विष्वास न होने के बावजूद योग षुरू करना पड़ा। नियमित योग करने से लक्ष्मी का माईग्रेन का दर्द आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गया। 2008 में लक्ष्मी पतंजली षिविर से जुड़ गई और योग प्रशिक्षण लेकर इसे जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। आज लक्ष्मी के जन–जन योग की मुहिम में स्कूल के बच्चे से लेकर गाँव की महिलायें और अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसकी शुरूआत वे प्रत्येक दिन अपने घर से करती हैं। इसके बाद स्कूल में

बच्चों को हर रोज योग सिखाया जाता है।

लक्ष्मी साह कहती हैं योग साधना है। इसलिए यदि आप भी जिन्दगी में कुछ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले योगी बनो, इसी से लोगों का बौद्धिक और आर्थिक विकास होगा। पहाड़ में गाँव के लोगों का बहुत अधिक धन बीमारियों के ईलाज में खर्च हो जाता है। वे मानती हैं कि पहाड़ की महिलाओं को योग का सबसे अधिक लाभ होगा। वे बताती हैं कि आज 5 हजार से भी अधिक बहनें उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, जिन्हें वे योग सिखाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों गाँवों की बहिनें उनसे योग के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। वे चाहती हैं कि उत्तराखण्ड के गाँवों को योग के माध्यम से रोगमुक्त किया जाय, तभी महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकेगा। जबकि समाज के असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करना उनके भीतर की संवेदनाओं से भरी समाज सेवा को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

उत्तराखण्ड राज्य में खरीफ 2021 में लागू

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मौसम खरीफ 2021 में लागू करने संबंधी राज्य अधिसूचना जारी कर दी गयी है। राजय सरकार द्वारा प्रदेश में योजना के ßिकृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/है0 888.00 रू0 कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/नाली 17.76 रू0 क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इश्योरेंन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया ए आई सी को अधिकृत किया गया है।

मौसम खरीफ 2021 के बीमा के लिए जनपद के कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम दर एवं बीमा राशि

1. धान फसल हेतु कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम दर 2 प्रतिशत
कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/है0 888.00 रू0
कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/नाली 17.76 रू0

2. मंडूवा फसल हेतु कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम दर 2 प्रतिशत
कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/है0 984.00 रू0
कृषकों द्वारा देय प्रीमीयम रू0/नाली 19.70 रू0

नोट : उपरोक्त प्रीमियम दर नियमानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सीडाइजड है।

बीमा करने की प्रक्रिया : सभी किसान जो संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल– चावल एवं मंडुवा उगा रहे हैं और उन्हें वित्तीय संस्थानों से फसली ऋण दिनांक 15.7.2021 तक स्वीकृत की गयी हो तथा कृषकों का ऋण खता 1.04.2021 से 15.07.2021 के मध्य क्रियाशील हो।

ऋण कृषकों को अनिवार्य रूप से आच्छादित किया जायेगा जब तक कि कृषक द्वारा सम्बन्धित मौसम में 15.07.2021 के एक सप्ताह पूर्व तक किसी भी समय लिखित रूप से संबंधित बैंक शाखाओं में योजना में सम्मिति न होने हेतु अपेक्षित घोषणा पत्र/प्रार्थना पत्र/ऑप्ट आउट फार्म प्रस्तुत नहीं किया गयाह हो।

जिन कृषक भाइयों ने ऋण नहीं लिया है यथा– अऋणी कृषक जो योजना का लाभ करना चाहते हैंख वे–

–बैंक की किसी भी निकटस्थ शाखा/सहकारी समिति (जहां उनका बचत खाता है)

ग्राहक सेवा केन्द्र/कामन सर्विस सेंट (सीएससी),

फसल बीमा पोर्टल (www-pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन क्राप इंश्योरेंस एप (Crop Insurace App)

एसआईसी के प्रतिनिधि/कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज के द्वारा प्रस्ताव पत्र एवं अआवश्यक प्रपत्र यथा– आधार कार्ड, भूमि संबन्धित दस्तावेज (खतौनी) एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा प्रीमियम राशि दिनांक 15.07.2021 तक जमा कराके व फसल बीमा पोर्टल (www-pmfby.gov.in) पर बीमा सम्बन्धित सूचना/Entry करवाकर अपनी संसूचित फसल का बीमा 15.07.2021 तक करवा सकते हैं।

किसान भाइ अगर कोई अन्य फसल उगा रहे हैं तो वे दिनांक 15.0702021 से दो दिन पूर्व तक जहां से उनका बीमा हुआ है, सूचना दे सकते हैं व अगर प्रीमियम की धनराशि में कोई अन्तर हो तो जमा कर सकते हैं।

प्रीमियम राशि केवल फसल बीमा पोर्टल (www-pmfby.gov.in) के भुगतान गेटवे (PayGov) के माध्यम से ही स्वीकृत की जायेगी। कृषक के खाते से प्रीमियम राशि कटौती की अन्तिम तिथि 15.07.2021 है अथवा राज्य अधिसूचना के अनुसार जिस किसान की बीमा सम्बन्धित सूचना फसल बीमा पोर्टल पर होगी (आधार कार्ड अनिवार्य), वही किसान फसल बीमा आच्छादन का पात्र माना जायेगा। बैंकों द्वारा भुगतान गेटवे (PayGov) के माध्यम से प्रीमियम राशि भेजने तथा फसल बीमा पोर्टल (www-pmfby.gov.in) पर बीमा सम्बन्धित सूचना/Entry करने की अन्ति तिथि 30.07.2021 है।

अधिक जानकारी के लिए न्यायपंचायत स्तरीय सहायक कृषि अधिकारी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, तथा मुख्य कृषि अधिकारी अथवा किसान काल सेन्टर- दूरभाष संख्या 01364233260 से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृषि विभाग रूद्रप्रयाग

नरेश कुमार
मुख्य विकास अधिकारी

मनुज गोयल
जिलाधिकारी

9 नवम्बर राज्य स्थापना दिवस,

दशहरा एवं दीपावली की
समस्त देश प्रदेश एवं
जनपद वासियों को

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद आन्दोलनकारियों को सहृदय भावभीन श्रद्धांजलि के साथ सभी को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनायें।

राजीव कंडारी

प्रदेश सचिव
उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी
देहरादून उत्तराखण्ड